20 जुलाई, 2022 * वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-7

राजस्थान सुजस

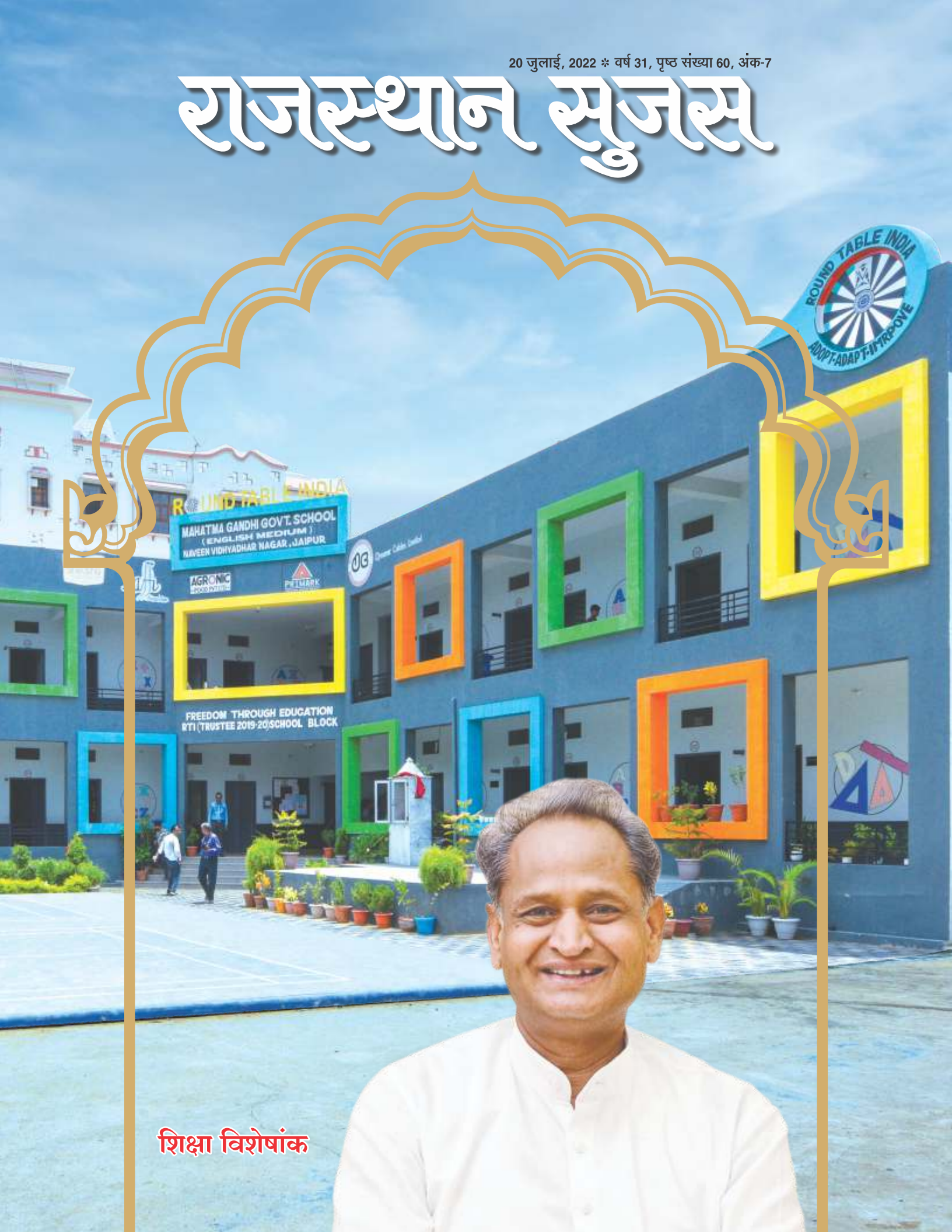

शिक्षा विशेषांक

भीलवाड़ा की फड़ चित्रकारी

राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन तथा उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारम्परिक, अनुष्ठानिक एवं कुंडलित चित्र, फड़ चित्र कहलाते हैं। 13 वीं शताब्दी की फड़ चित्रकला केवल चित्र भर नहीं मानी जाती। फड़ चित्रण के माध्यम से लोक देवताओं व लोक नायकों की कथा कही जाती है।

फड़ चित्र लंबी पेंटिंग होती है, जो लगभग 20 से 36 फीट लंबी तथा 5 फीट तक चौड़ी होती है। फड़ चित्र प्राकृतिक रंगों से तथा हाथ के बुने हुए मोटे कपड़ों पर उकेरे जाते हैं। जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के संग्रहालयों में भीलवाड़ा की फड़ चित्रकारी राजस्थान का गौरव बढ़ा रही है।

आलेख : हेमन्त छीपा । छाया : पंकज त्रिपाठी

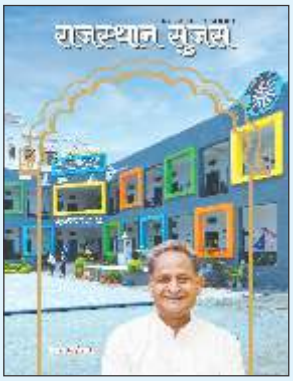

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

आवरण छाया
अशोक गुरावा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 07 | जुलाई, 2022

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य...	18
राजीव गांधी स्कॉलरशिप...	19
बच्चों के सर्वांगीण विकास...	20
स्कूल शिक्षा रैंकिंग में श्रीगंगानगर अव्वल	22
प्रदेश में प्रगति सोपान पर उच्च शिक्षा	24
राजस्थान की गौरवमयी गाथा	27
सांगीतिक परम्परा से समृद्ध धराः मरुधरा	37
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय...	38
एजुकेशन सिटी: अजमेर	39
उदयपुर का अनूठा राजकीय विद्यालय	40
शिक्षा के लिए ग्रामीणों ने किया दान...	44
राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम...	47
बेटियों को आगे बढ़ने की 'शक्ति' देता...	48
भीलवाड़ा : शत-प्रतिशत महिला मेट...	50
आवासीय विद्यालय	51
स्वच्छता प्रबंधन	52
नवाचार	53
विरासत	54
शिशु विकास	55
शिक्षा विकास	56
खेल-खिलाड़ी	57
रंगमंच	58
धरोहर	59
तस्वीर बदलाव की	60

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर...

05

HOW GOVT ENGLISH MEDIUM...

12

साक्षात्कार

14

बातचीत

16

फोटो फीचर

30-31

सामयिकी

32

योजना

42

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

राजस्थान में शिक्षा का बदलता परिदृश्य

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान संभावनाओं से भरा प्रदेश है। भौगोलिक चुनौतियों और विविधताओं के बावजूद राज्य में बालक-बालिकाओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विभिन्न नवाचार किए हैं। इससे राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य बदल रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए राज्य का विद्यार्थी अब तैयार हो रहा है।

यहां के राजकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों का शुभारंभ और विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किए गए प्रयासों से राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आई है। इन सब प्रयासों से जन समुदाय का विश्वास और रुझान राजकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ा है। अब राजकीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावक और बालक-बालिकाएं प्रयासरत रहते हैं। राजस्थान के विकास के लिए यह सुखद संकेत है।

राजस्थान सुजस का जुलाई माह का अंक शिक्षा को समर्पित किया गया है। आशा है यह अंक भी आपको पसंद आएगा। आपके सुझाव राजस्थान सुजस का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उदीयमान राजस्थान

आशाराम खटीक
जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान राज्य पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बुलन्दियां छू रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशलतम नेतृत्व एवं शिक्षा से रोशनी की दूरदर्शी सोच के साथ आज प्रदेश शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन कर अग्रणी राज्यों में शुमार है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों, नीतिगत निर्णयों, प्रगतिशील कार्यक्रमों, योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन से राजस्थान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऊंचाइयां छू रहा है। विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों का जयपुर, कोटा, अजमेर व सीकर में ज्ञानार्जन हेतु आगमन किसी भव्य शैक्षिक पर्यटन की परिकल्पना से कम नहीं है। वर्तमान में राजस्थान प्रदेश का यह शैक्षिक परिदृश्य शिक्षार्जन के सांस्कारिक उद्देश्यों ''ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान'' की उक्ति को चरितार्थ करता प्रतीत होता है।

देशभर के शैक्षिक पटल पर प्रदेश शीर्ष पर

स्कूली शिक्षा में देशभर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में राजस्थान ने 1+ रैंकिंग हासिल की है। फिट इण्डिया मूवमेन्ट में भी प्रदेश अव्वल रहते हुए प्रथम स्थान पर रहा है। इन्स्पायर अवॉर्ड योजना में भी राजस्थान देश में पहले स्थान रहा है। शैक्षिक स्थिति के आकलन हेतु आयोजित एनएएस-2021 में राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही।

''नो बैग डे'' ने किया बस्ते का बोझ कम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नौनिहालों की पीठ पर लदे बोझ की संवेदना को भांपते हुए प्रत्येक शनिवार को ''नो बैग डे'' का शुभारम्भ 15 अक्टूबर, 2020 से आरम्भ करवाया। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां शिक्षा मनोविज्ञान के अनुरूप गतिविधि आधारित शिक्षण की महत्ता को इस स्तर तक समझा गया। विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं सहज प्रतिभा प्रदर्शन, सीखने की प्रक्रिया रूचिकर एवं भयमुक्त हो, इसके लिए शनिवार को बिना बैग एवं पुस्तकों के विद्यालयों में अधिगम को तरजीह दी गई। शनिवारीय शैक्षणिक

गतिविधियों का थीम आधारित चार्ट लागू किया गया।

प्रतिमाह शनिवार के थीम

- **पहला शनिवार – राजस्थान को पहचानो**
- **दूसरा शनिवार – भाषा कौशल विकास**
- **तीसरा शनिवार – खेलेगा राजस्थान**
- **चौथा शनिवार – मैं भी हूं वैज्ञानिक**
- **पांचवां शनिवार – बाल सभा : मेरे अपनों के साथ**

शहादत को सम्मान

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे, हर बरस मेले।
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।।

मां भारती की रक्षार्थ अपने सर्वस्व का समर्पण करने वाले रणबांकुरों और जांबाज जवानों का स्मरण कराती यह पंक्तियां हमें शहीद स्मारकों पर देखने को मिलती है, जो हमें जोश और प्रेरणा से भर देती है। वीरगति को प्राप्त हुए ऐसे ही सपूतों और अमर शहीदों की याद में उनके त्याग को सम्मान देने की अद्वितीय सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाए। राजस्थान में शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 160 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा 144 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किए गए हैं।

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के नवाचार के प्रति जनमानस का रूझान इसकी सफलता को इंगित करता है। राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बालिकाओं से मुखतिब होते हुए

से प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इन विद्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019-20 में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इनका सफलतापूर्वक संचालन आरम्भ किया गया और वर्ष 2020-21 में 172 ब्लॉक मुख्यालयों पर भी ये विद्यालय सुसंचालित किए जा रहे हैं।

अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों/गांवों में भी आगामी दो वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के 1206 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिनमें से 533 विद्यालय एवं शहरी क्षेत्र के 11 विद्यालय रूपान्तरित किए जा चुके हैं, वहीं 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं सत्र 2021-22 से प्रारम्भ की जा चुकी हैं। 563 महात्मा गांधी विद्यालयों में भी सत्र 2022-23 का संचालन जारी है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत "राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लॉन्च एवं फील्ड ओरिएंटेशन समारोह को संबोधित करते हुए

राजीव गांधी करियर पोर्टल

कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में करियर के प्रति जागरूकता, विषय चयन, रोजगार के अवसरों की जानकारी एवं क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक परिदृश्य में हो रहे बदलावों की जानकारी के लिए राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल संचालित किया जा रहा है।

हाइजीन और स्वच्छता

बच्चों में हाइजीन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के 2 हजार 400 राजकीय विद्यालयों में स्कूल हाइजीन एज्युकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में हाइजैनिक वातावरण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व अभियान के रूप में जनजागृति की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

मिड डे मील प्रोग्राम

कोविड-19 के दौरान मिड डे मील के रूप में 66 लाख से अधिक विद्यार्थियो को विद्यालय स्तर पर दाल, तेल, मसाले के कॉम्बो पैकेट्स आदि उपलब्ध कराये गए, जिन्हें अभिभावकों द्वारा भी सराहा गया है।

कोविड वैश्विक महामारी में भी निर्बाध शिक्षा

''आओ घर में सीखें'' कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित स्माइल (SMILE=Social Media Interface for Learning Engagement) के तहत वाट्सएप द्वारा विद्यार्थियों व शिक्षकों को दैनिक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। 20 हजार से अधिक ग्रुप्स बनाकर पाठ्यसामग्री की पहुंच सुनिश्चित की। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। ई-कक्षाएं लगाकर वर्चुअल माध्यम से लर्निंग कण्टेंट तथा दूरदर्शन राजस्थान के माध्यम से टेलीविजन पर शिक्षादर्शन कार्यक्रम का प्रसारण, रेडियो पर शिक्षावाणी कार्यक्रम से पाठ्यक्रम आधारित 55 मिनट की पाठ्यसामग्री का प्रसारण, शिक्षक संवाद के अन्तर्गत फोन कॉल्स एवं मिशन समर्थ के जरिए बधिर एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई।

शिक्षक सम्मान

शिक्षक ही समाज में राष्ट्र निर्माता के रूप में भावी पीढ़ी को तैयार करता है। इसी सोच को सार्थकता देते हुए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिक्षकों के सम्मान की पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के 1 हजार 101 शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। राज्यस्तर पर 99 शिक्षकों (प्रत्येक जिले से हर कक्षा समूह में एक-एक) को 21 हजार रुपये से, जिला स्तर पर 3 शिक्षकों को (जिले से हर कक्षा समूह में एक-एक) को 11 हजार रुपये से तथा ब्लॉक स्तर पर 3 शिक्षकों (ब्लॉक स्तर से हर कक्षा समूह में एक-एक) को 5 हजार 100 रुपये से सम्मानित किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर भी सम्मानित शिक्षकों को नि:शुल्क बस यात्रा एवं रियायती दरों पर भूखण्ड की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति भी समय-समय पर की जा रही है।

शैक्षिक सुदृढ़ीकरण

स्मार्ट कक्षाओं एवं आइसीटी लैब्स का विस्तार जारी है। प्रदेश के 101 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और 11 हजार 674 आईसीटी लैब्स स्थापित किए गए हैं। साथ ही 8 हजार 766 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और 398 आईसीटी लैब बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 123 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। एक हजार 22 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक एवं 1 हजार 121 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 4 हजार 421 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने का निर्णय कर इस

दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। 608 अतिरिक्त संकाय एवं कृषि संकाय प्रारम्भ किए गए हैं। 300 अतिरिक्त विषय भी प्रारम्भ किए गए हैं जिससे प्रदेश का शैक्षणिक विस्तार आकार पा रहा है।

शाला संबलन एप

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हुए शाला संबलन एप निर्मित किया गया है। इसी एप के माध्यम से कम समय में सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रेक किया जा रहा है।

शाला दर्पण पोर्टल

स्टाफ विंडो पर विभाग के कार्मिकों के लिए विभिन्न आवेदनों यथा विदेश यात्रा, परीक्षा अनुमति, अवकाश प्रार्थना पत्र, विभिन्न साक्षात्कार आवेदन, एपीएआर आदि की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार योजना एवं विस्तार पाते शैक्षिक आयाम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के सहयोग से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरूआत की गई जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर 6 विद्यालय, जिला स्तर पर 66 विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर 301 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विभिन्न नियमों में आवश्यकतानुसार 50 साल बाद शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव कर शिथिलता बरतते हुए शिक्षकों को राहत दी गई है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-प्रथम के पद एनकैडर किए गये है। साइबर सुरक्षा जागरूकता व्यापक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कम्पनियों, गैर सरकारी संगठनों, दानदाताओं, भामाशाहों व आमजन के सहयोग हेतु ऑनलाइन पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष एवं ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से लगभग 263 करोड़ से अधिक का सहयोग विद्यालयों को प्राप्त हुआ है। इस

बच्चों को आर्शीवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

जनसहभागिता या जनसहयोग से निश्चित रूप से आमजन एवं संस्थाओं का राजकीय विद्यालयों से जुड़ाव ओर मजबूत हुआ है, जो प्रदेश के शैक्षिक वातावरण के लिए सर्वथा अनुकूल, उपयोगी एवं सकारात्मक है।

- **शिक्षा व स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता**
- **सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील**
- **अगला बजट होगा युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित**
- **मुख्यमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया ब्रिज कोर्स**
- **कोरोना के कारण गत सत्रों में हुए लर्निंग लॉस की होगी भरपाई**

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ''राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम'' कार्यक्रम लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम ''राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम'' शुरू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आयोजित ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान व आनन्दपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन करवाया जाएगा।

शिक्षा नवाचारों में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट

राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अद्भुत नवाचारों से देश में मॉडल स्टेट के रूप में पहचान बना रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम का शुभारम्भ करते हुए

बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

मीडियम विद्यालयों का गठन और दक्षता आधारित शिक्षण का विजन दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में न केवल शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है बल्कि अकादमिक प्रगति भी हुई है। कोविड के कारण हुई नौनिहालों की शैक्षिक क्षति की भरपाई के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से इस ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस ब्रिज कोर्स में रटने की बजाए सीखने पर बल दिया जाएगा।

ब्रिज कोर्स से राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम

ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम तीन माह में 4 कालांश तथा शेष सम्पूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित रहेंगे। योजनान्तर्गत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित कार्यपुस्तिकाएं तैयार की जाएगी तथा वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नियमित शिक्षक-अभिभावक बैठकों के साथ विद्यार्थियों के दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे तथा कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंगएड एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कोरोना काल में छोटे बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है। सरकार द्वारा शिक्षा जारी रखने के लिए किए गए डिजिटल नवाचारों के बावजूद दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे थे। ब्रिज कोर्स का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों का शैक्षणिक स्तर वर्तमान कक्षा के अनुरूप लाना है। इससे उन्हें भविष्य में तकलीफ नहीं आएगी।

युवा, विद्यार्थियों व शिक्षा को समर्पित होगा आगामी बजट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का विजन है कि अगला बजट राज्य के युवाओं व विद्यार्थियों को समर्पित होगा। राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा उनके अशैक्षणिक दायित्वों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे ब्रिज कोर्स का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकें। शिक्षा व स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। इन दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य होने पर ही देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का विकास हो सकता है।

कोरोना काल में छोटे बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है। सरकार द्वारा शिक्षा जारी रखने के लिए किए गए डिजिटल नवाचारों के बावजूद दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे थे। ब्रिज कोर्स का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों का शैक्षणिक स्तर वर्तमान कक्षा के अनुरूप लाना है। इससे उन्हें भविष्य में तकलीफ नहीं आएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य उपलब्धियाँ

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों के लिए विद्या संबल योजना लागू की गई है।
- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जानी है। इस संबंध में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2021 का आयोजन करवाया जाकर रीट-2021 लेवल-1 के 15500 पदों में से 15178 जिला आवंटन आदेश जारी किये जा चुके है। शेष 46500 पदों हेतु रीट परीक्षा 23.7.2022 व 24.7.2022 को आयोज्य है।

- 162 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये व 1177 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।
- 1127 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में, 426 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में तथा 4441 विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है।
- नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अभिभावकों की आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गई।
- आरटीई के तहत गत तीन वर्षों में 18.80 लाख विद्यार्थियों के लिए 1274.78 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्भरण किया गया।
- राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)'' कक्षा एक से बारहवीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 205 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले गए जिनमें 87,331 विद्यार्थी नामांकित हैं। अब तक राज्य में 1206 विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जा चुके हैं।
- आर्थिक पिछड़े वर्ग की सामान्य बालिकाओं को 802 स्कूटियों का वितरण किया जायेगा।
- 10,33,794 साइकिलें वितरित की जा चुकी है।
- राजस्थान में नवाचार अपनाते हुए भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जो शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्व देते हुए प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे को प्रारम्भ कर रहा है।
- समस्त प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का सत्र 2021-22 से पोर्टल आरम्भ किया गया है। वर्ष 2021-22 के समस्त आवेदन से संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन भरवाये गये हैं।
- स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा में 31,433 एवं प्रारम्भिक शिक्षा में 42,796 कुल 74,229 पदों पर नियुक्ति एवं 3010 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के तहत 1620.06 लाख पुस्तकों का वितरण किया गया तथा 16813.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया हैं।
- 2916 विद्यालयों एवं 282 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किए गए।
- 35 मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण किया

बाल संरक्षण संकल्प यात्रा समारोह में विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

गया।

- 4 मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावास एवं 4 नवीन केजीबीवी का निर्माण किया गया।

- राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 14,051 कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहद् मरम्मत कार्यों हेतु रुपये 1581.83 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। 10,881 कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण, 11 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण एवं 80 विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण। 2617 कक्षा-कक्षों एवं 11 नवीन विद्यालयों का भवन निर्माण एवं दो विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है। रुपये 972 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना के तहत सत्र 2020-21 हेतु चयनित 22 ब्लॉकों में से 19 ब्लॉकों में छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। सत्र 2021-22 के लिये चयनित 23 ब्लॉकों में भूमि का आंवटन पूर्ण।

- महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने तथा जन सामान्य में पढ़ने की रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से पूर्व में संचालित 8,869 महात्मा गांधी पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14,970 किया जाने की प्रक्रिया जारी है। 11,341 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों के संचालन के आदेश जारी।

- 2244 बालिकाओं को 19.55 करोड रुपये के इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किये।

- आपकी बेटी योजनान्तर्गत ''गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो'' एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है, को लाभान्वित किया जाता है। 55,832 बालिकाओं को राशि रुपये 11.09 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

- बालिका प्रोत्साहन योजना में 1.86 लाख बालिकाओं को राशि रुपये 93.15 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

- गार्गी पुरस्कार योजना अन्तर्गत 17.12.2018 से आदिनांक तक कुल 2.39 लाख बालिकाओं को 71.82 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

- वर्ष 2019-20 में 726 शिक्षकों को पुरस्कृत राशि रूपये 58.17 लाख वर्ष 2020-21 में 849 शिक्षकों को पुरस्कृत राशि रुपये 64.88 लाख एवं वर्ष 2021-22 में 900 शिक्षकों को पुरस्कृत राशि रुपये 67.48 लाख पुरस्कार के रूप में दिये गये।

- 162 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं 132 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किये गये।

- 51 वरिष्ठ उपाध्याय, 50 प्रवेशिका, 07 उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया एवं 05 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये।

बाल संरक्षण संकल्प यात्रा में विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

HOW GOVT ENGLISH MEDIUM SCHOOLS TURNED THE EDUCATION SCENARIO IN RAJASTHAN AROUND

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), कोटा में इंडोर गेम्स खेलते हुए विद्यार्थी

Rahul Sharma
Principal, MGGS, Multipurpose, Kota

Come July and the government teachers could be seen moving around, knocking the doors, convincing the parents to put their children in government schools. This has been, hitherto, the common phenomenon in the schools as the education department machinery launches its admission drive at the beginning of new session.

However, the year 2019 proved to be a milestone of sorts when the present state government under the leadership of Hon'ble Chief Minister Shri Ashok Gehlot came up with Mahatma Gandhi Government English Medium Schools for the first time in the state to commemorate the 150th birth year of the Father of the Nation.

In the first year, one school at each district headquarters was converted to English medium. In Kota, Multipurpose School was chosen. The huge public response to this initiative went far beyond what anyone could have anticipated. People started queuing up to get their children admitted to this school. The number of applications received for admissions far outnumbered the number of available seats, necessitating lotteries for all the classes.

So far as workforce of these schools is concerned, starting from Principal all the posts were filled through a stringent interview process. Apart from subject knowledge, the in-service teachers who applied for various posts were assessed for their English language proficiency and communication skills. The teachers, thus selected, came with a zeal to prove their mettle. They gave their best to ensure success of this flagship scheme of state government.

The effort, the staff of MGGS Multipurpose Kota put in, was reflected in the performance of the students who not only excelled academically but also displayed their talent in various competitions, sports and co-curricular activities. Three students of this school got selected for INSPIRE Award (sponsored by the Department of Science and Technology, Government of India) in the very first session. Six students (largest in district) secured first position at district level Science Fair in 2021-22. One of them secured first position at state level and will now participate at national level. Fifty students made into Guinness World Records for Sundial assembling.

Students excelled at sports field also. Over the course of last three years, 40 students represented Kota district at state level in various sports. In the state level event of Yoga Olympiad for English Medium Schools, a student of this school bagged two silver and one bronze medal. Three students brought laurels to

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), कोटा में सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए विद्यार्थी

school by winning Gold Medal at State Level Wushu Championship sub-junior category. One of them won Gold at National Level, making not only school or district but the whole state proud. Two girls from this school won Gold Medals in kick boxing at state level.

Thanks to the commitment of staff and enthusiasm of students, NCC Air Wing was approved out of turn with an allotted strength of 50 cadets per year. Many of them have had experience of flying an aircraft also. School organized an educational tour recently where many of these cadets and students visited Abhay Command Centre, Hi-tech Police Control Room and learnt how law and order situation is effectively monitored by the district police administration.

Taking these achievements into account, Govt of Rajasthan decided to open more such schools at block and panchayat levels to provide quality English medium education to all sections of society. As of now,15 schools have been converted to English medium in Kota district and handling the admission rush.

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), कोटा के कम्प्यूटर लैब में विद्यार्थी

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), कोटा में शिक्षक व विद्यार्थी पक्षियों के लिए परिंडे बांधते हुए

शिक्षा से चहुंमुखी समृद्धि की ओर पथारूढ़ राजस्थान...

"राजस्थान प्रदेश पूरे देश में शिक्षा की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अंग्रेजी भाषा की वैश्विक रूप से बढ़ती जरूरत एवं रोजगार एवं स्वरोजगार की दृष्टि से इसकी मांग व महत्ता की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इनमें प्रवेश हेतु आमजन, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकगण में होड सी मची होना इस नवाचार की सफलता है। बालक की मुस्कान राष्ट्र की शान होती है। नो बैग डे से बच्चों में शनिवार को खुशहाल एवं खुशनुमा माहौल मिला है।"

शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला से शैक्षणिक विकास पर
जनसम्पर्क अधिकारी आशाराम खटीक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश...

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है। इसका क्या फायदा नजर आता है आपको?

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार के लिए लागू की गई है। इसके तहत सप्ताह में दो दिवस दूध उपलब्ध कराया जाएगा। बालक की मुस्कान राष्ट्र की शान होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। निश्चित रूप से इस कदम से नौनिहाल हष्ट-पुष्ट होंगे एवं भावी कर्णधारों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिल सकेगा।

हाल ही में तबादलों हेतु गाइडलाइन (मार्गदर्शिका) लागू की गई है, इसके क्या भावी परिणाम रहेंगे?

शिक्षक व्यक्ति के चरित्र निर्माण की महत्त्वपूर्ण इकाई है। चरित्रवान नागरिकों से ही सभ्य समाज व समुन्नत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने समय-समय पर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते शिक्षकों के तबादलों को सरलीकृत एवं सुगम बनाने के लिए हाल ही में गाइडलाइन जारी की है। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षकों में तबादलों को लेकर पारदर्शिता आएगी और शिक्षकगण की समस्याओं का यथोचित समाधान होगा।

यूपीए सरकार के समय हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रदेश में शैक्षिक उन्नयन एवं सुखद परिदृश्य का परिचायक है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से युवा स्कॉलर्स को क्या लाभ मिल पाएंगे?

युवा राज्य सरकार की नीतियों का केन्द्र बिन्दु हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। अब सरकारी खर्च पर युवा विदेशों के 150 विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों से उच्च शिक्षा से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसमें भी छात्राओं को 30 प्रतिशत आरक्षण एवं 8 लाख से कम आयवर्ग के पात्र अध्येताओं को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें तथा विदेशों में अध्ययन के साथ ही जॉब्स के अवसर उपलब्ध हों इसलिए यह योजना लागू की गई है।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में छात्र एवं अभिभावकगण की रूचि से निजी शिक्षण संस्थान भी स्तब्ध है, क्या सोचते है आप?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अंग्रेजी भाषा की वैश्विक रूप से बढ़ती जरूरत एवं लोगों में इसके प्रति रूझान, रोजगार एवं स्वरोजगार की दृष्टि से इसकी मांग व महत्ता की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में आमजन, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकगण में होड सी मची होना एवं प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा इस नवाचार की सफलता को दर्शाता है। इसी चालू शिक्षा सत्र में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शालाओं में नर्सरी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जा रहा है।

विगत समय में कोविड-19 से उपजी विकट परिस्थितियों एवं लॉकडाउन में अध्ययन-अध्यापन के तौर-तरीकों में परिवर्तन किया है, ऑनलाइन एवं वर्चुअल माध्यमों से शिक्षण के लिए सरकार की क्या भावी कार्य योजना रहेगी?

आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स, इन्टरनेट ऑन थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी आदि के जरिए ऑनलाइन स्टडी व्यापक रूप से बढ़ी है, इससे शिक्षण के विभिन्न आयामों में वृहद स्तर पर बदलाव आया है। आज शिक्षा का विश्वस्तर पर स्कॉप है। औपचारिक शिक्षा के साथ ही कौशल विकसित कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर युवाओं को कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य है।

युवा राज्य सरकार की नीतियों का केन्द्र बिन्दु हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। अब सरकारी खर्च पर युवा विदेशों के 150 विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों से उच्च शिक्षा से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।

चरित्रवान नागरिकों से ही सभ्य समाज व समुन्नत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन कौशल व रोजगार के साथ ही विदेशों में अध्ययन तथा जॉब्स के अवसर हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना लागू की गई है।

सरकार ने शनिवार को "नो बैग डे" घोषित किया है, इस नवाचार से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नो बैग डे से बच्चों में शनिवार को खुशहाल एवं खुशनुमा माहौल मिला है। ज्ञानार्जन के साथ ही साथ न सिर्फ इस नवाचार से बालक एक्सट्रा केरीकुलर एक्टीविटी से जुड़कर सक्रिय सहभागिता निभा पा रहे हैं अपितु उनका रूझान खेल एवं अन्य अभिरूचिपरक अधिगम कार्यों में भी निश्चित रूप से बढ़ा है।

प्रदेश सतत रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शैक्षिक विकास की इस गति में और प्रगति हो, इसके लिए सरकार की ओर से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?

सरकार शिक्षा को लेकर सदैव सजग रही है। प्रदेश के नौनिहाल एवं कर्णधार-युवा सभ्य नागरिक बनें और समाज व राष्ट्र के प्रति उनमें दायित्व बोध होगा तभी वे देश-प्रदेश का भविष्य तय कर पाएंगे। यूपीए सरकार के समय हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, इसी दृष्टिकोण से अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रदेश में शैक्षिक उन्नयन एवं सुखद परिदृश्य का परिचायक है। आगे भी अध्ययन-अध्यापन एवं शैक्षणिक विकास के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर लगभग चार हजार सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किये गए हैं। 500 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय, 200 प्राथमिक विद्यालय रेगिस्तानी इलाकों में तथा 500 नये विषय एवं संकाय खोले जा रहे हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सर्वांगीण विकास के पथ पर पथारूढ़ होगा।

हमारा प्रयास
शिक्षा प्रदेश के गांव–ढाणी तक पहुंचे

“शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सम्भावनाओं से भरा प्रदेश है। भौगोलिक चुनोतियों एवं विविधताओं के बावजूद भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही राजस्थान के विद्यार्थियों का है। राजस्थान ने गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम मजबूती से आगे बढाये हैं। हमारा प्रयास है कि शिक्षा प्रदेश के गांव–ढ़ाणी तक पहुंचे और कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं रहे।”

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा श्री पी.के. गोयल से
अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क अरूण जोशी द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश...

आप राजस्थान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को किस प्रकार देखते हैं ?

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सम्भावनाओं से भरा प्रदेश है। भौगोलिक चुनोतियों एवं विविधताओं के बावजूद भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही राजस्थान के विद्यार्थियों का है। राजस्थान ने गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाये हैं। राजस्थान भामाशाहों का प्रदेश है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने में भामाशाहों ने सदैव आगे होकर कार्य किया है।

NEP-20 के क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान की क्या तैयारी है ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की क्रियान्विति की दिशा में राज्य के कदम काफी आगे बढ़ चुके हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन एवं समूहवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। राज्य में ECCE के लिए लगभग 40,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का समन्वयन विद्यालयों के साथ किया जा चुका है तथा 1,033 बाल वाटिकाएं प्रारम्भ की जा रही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। NEP-20 के निर्देशों के अनुसार सभी ड्रॉप आउट बालकों को विद्यालय से जोड़ते हुए सकल नामांकन अनुपात शत–प्रतिशत करना, शिक्षक–शिक्षा, शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग एवं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर कार्य प्रगति पर है।

शिक्षा की पहुंच एवं नामांकन की दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं ?

विगत सत्र में राज्य में राजकीय विद्यालयों का नामांकन 98.5 लाख से अधिक रहा और हमारा प्रयास है कि इस सत्र में नामांकन 1 करोड़ से अधिक हो। विद्यार्थियों को उनके परिवेश में समीपस्थ स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य के सभी 4 हजार से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को तथा 250 अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यथा आवश्यकता सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा रहा है। रेगिस्तानी 04 जिलों में 200 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं एवं 500 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 500 अतिरिक्त संकाय/विषय खोले जा रहे हैं। हमारे प्रयासों से समुदाय का विश्वास राजकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ा है। विगत 03 वर्षो में राज्य में नामांकन में 16 लाख से अधिक की वृद्धि होना इसका परिचायक है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा राज्य के गांव–ढाणी तक पहुंचे और कोई भी बालक अनामांकित नहीं रहे। विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य–पुस्तकें, कक्षा 1–8 तक के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पोशाक उपलब्ध करवाई जा रही है एवं पौष्टिक मध्यान्ह भोजन के साथ ‘‘बालगोपाल’’ योजना के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है।

कोरोनाकाल में विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवधान की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के क्या प्रयास हैं।

कोरोना काल में विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़े रखने के लिए स्माइल 0.1, 0.2 एवं 0.3, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा, हवामहल, दूरदर्शन आदि के माध्यम से प्रयास किये हैं। इस दौरान हुये Learning Losses की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में विशेष घोषणा की है, जिसके तहत हम ''राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम'' ब्रिज कोर्स कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं।

क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों की पूर्ति के लिए क्या प्रयास है?

उपलब्धियां सदैव ही चुनौतियों को बढ़ा देती है लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। विगत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 79,000 से अधिक नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं एवं 94 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। शीघ्र ही इन पदों पर भी नियुक्तियां प्रदान की जा सकेंगी। तात्कालिक शिक्षण व्यवस्था के लिए सेवानिवृत शिक्षकों एवं पात्र युवाओं को विद्या सम्बल योजना के तहत विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियोजित किया जा रहा है। विभिन्न पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न की जा रही है ताकि पदों की पूर्ति की जा सके। हमारा विश्वास है कि विद्यार्थियों के शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

शिक्षा में तकनीकी के समावेश पर राजस्थान में क्या किया जा रहा है ?

शिक्षा में तकनीकी के अनुप्रयोग को लेकर राजस्थान में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में अध्ययनरत सभी स्कूली विद्यार्थियों एवं शिक्षा विभाग के कार्मिकों का डेटाबेस संधारित किया जाता है। यही नहीं शिक्षक/विद्यार्थी उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, टी.सी., शिक्षकों का ए.पी.ए.आर., आश्वासित कैरियर प्रोग्रेस के प्रकरण, कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति कार्य मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालयों के कार्य शाला दर्पण पर सम्पादित किये जा रहे हैं।

विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

राजस्थान का विस्तार एवं भौगोलिक परिस्थितियों अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हैं और विद्यालय दूरस्थ गांवों और ढाणियों में स्थित है। विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सत्र 2019-20 में 2468.76 करोड़ रुपये के 7199 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 1730.77 करोड़ रुपये के 6326 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों में मुख्यत: विद्यालय सुदृढ़ीकरण कार्य, नवक्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण कार्य, मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावास का निर्माण, नवीन केजीबीवी निर्माण एवं विद्यालय भवनों में वृहद मरम्मत के कार्य शामिल है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सीएसआर के तहत कई विद्यालयों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गोद लेकर आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन/कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में भामाशाहों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि राजकीय विद्यालयों को दान की गई है।

बालिका शिक्षा क्षेत्र में क्या नवाचार किये जा रहे हैं?

बालिका शिक्षा की पहुंच गांव-ढाणी तक सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य में 400 से अधिक बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। राज्य में संचालित 1846 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से यथा आवश्यकता सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया जा रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

खेल मैदानों के विकास के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर हमारा विशेष जोर है। राज्य में पहली बार कक्षा 11 व 12 में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय के रूप में सत्र 2022-23 से 249 विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। शारीरिक शिक्षकों के 5,846 नवीन पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। खेल मैदानों के विकास के लिए ''मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम'' योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विजेताओं को सीधे ही सरकारी सेवा में नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर उत्कर्ष श्रेणी में आए जिलों के बारे में क्या कहना है?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सतत प्रयासों का ही प्रतिफल है कि राजस्थान सत्र 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट स्थान बना पाया। राष्ट्रीय स्तर पर केवल राजस्थान के ही तीन जिले सीकर, झुंन्झुनूं एवं जयपुर उत्कृष्ट श्रेणी एवं 24 जिले अति उत्तम श्रेणी में रहे। ये उपलब्धि सभी राजस्थानवासियों के लिए गर्व का विषय है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजना की विशेषताओं के बारे में बतायें?

वर्तमान समय वैश्वीकरण का है। शिक्षा में सतत् विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ सरेखण करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ सरेखन कर अपना भविष्य तलाश सकें। राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)'' कक्षा एक से बारहवीं तक स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया। इन विद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। योजना को प्रभावी बनाने हेतु दृष्टि पत्र (VISION-2028) तैयार किया गया है।

विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम

अविनाश चौहान
जालोर

महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय चोरु, सायला, जालोर में प्रवेश उत्सव मनाते हुए शिक्षकगण

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। परन्तु अधिक फीस के कारण गरीब एवं मध्यमवर्ग चाह कर भी अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के युग मे अंग्रेजी का महत्त्व किसी से छुपा नहीं है। वैश्विकरण के इस युग में अंग्रेजी का ज्ञान हर किसी के लिये व्यापार और रोजगार के नये-नये अवसर उत्पन्न कर सकता है। अंग्रेजी का ज्ञान आज के युवा के लिये आवश्यक हो चला है। राज्य के सरकारी हिन्दी विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से होते हैं, जो उच्च अध्ययन में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चों के साथ कदम ताल मिलाने में भारी कठिनाई महसूस करते हैं।

राज्य के विद्यार्थियों की इसी कठिनाई को राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समझा और वर्तमान युग में अंग्रेजी का महत्व समझते हुये राज्य के विद्यार्थियों को भी इसी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की मन में ठान कर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा एक से बाहरवीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया। जिसके तहत राज्य में जिला मुख्यालयों व ब्लॉक स्तर पर चरणबद्ध रूप से इनकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया।

जालोर जिला मुख्यालय पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जयंती के अवसर पर इसे प्रारम्भ किया गया। इसे उत्कृष्टता के केन्द्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारम्भ करने से अब समाज के हर तबके का रूझान राजकीय विद्यालयों की तरफ बढ़ रहा है।

जिले मे स्थापित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की अप्रत्याशित मांग को देखते हुये सत्र 2020-21 से ब्लॉक स्तर पर भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है। जालोर जिले मे वर्तमान मे कुल 15 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हो रहे हैं।

महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, भीनमाल, जालोर की छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हुई

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में जिले में ब्लॉक स्तर पर सियाणा, आहोर, जसवंतपुरा, भीनमाल, बी ढाणी (सांचौर) एवं चितलवाना में एवं वर्ष 2021-22 में भाद्राजून की ढाणी (आहोर), मालवाडा (रानीवाडा), चौराऊ (सायला), हापू की ढाणी भालनी (भीनमाल), करडा (रानीवाडा), करवाडा (रानीवाडा) व दासपा (भीनमाल) में तथा वर्ष 2022-23 में तेजा की बेरी (सायला) में सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किये गये हैं। अब समाज के हर तबके का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलवाने का सपना पूरा होगा तथा विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिये ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होंगे।

जिला मुख्यालय पर सत्र 2019-20 में कक्षा एक से आठवीं तक के लिये अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय को रूपान्तरित किया गया था तथा आगामी वर्षो मे क्रमशः कक्षा नवमी से बारहवीं संचालित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान मे जिला मुख्यालय पर संचालित विद्यालय में कक्षा एक से ग्यारहवीं तक के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से लाभान्वित होकर सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे है। ●

महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, जालोर में विद्यालय आगमन पर छात्र-छात्राओं का अभिवादन करती शिक्षिकाएं

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना

200 मेधावी विद्यार्थियों के विदेश में उच्च अध्ययन का पूरा खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एवं स्टेनफोर्ड जैसे दुनिया के नामी 150 विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों में अध्ययन कर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे विद्यार्थी।

आशाराम खटीक
उप-सम्पादक, सुजस

''युवा राज्य सरकार की नीतियों का केन्द्र बिन्दु हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है।''

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के चुनिंदा लब्धप्रतिष्ठ 150 विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधाएं मुहैया करा रही है। गौरतलब है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस (आरजीएस) योजना की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी की जयंती, सदभावना दिवस 20 अगस्त, 2021 को की गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उच्च शिक्षा के प्रति दूरदृष्टि पर आधारित इस नवाचार से प्रदेश के अध्ययन-अध्यापन से जुड़े युवा स्कॉलर्स, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकगण आदि में उत्साह है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त, 2021 को इस योजना की घोषणा की। उच्च शिक्षा विभाग ने विस्तृत नियम बनाकर हाथोंहाथ यह योजना तत्काल लागू की। इस योजना के तहत ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एवं स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे दुनिया की नामचीन 150 संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरल स्तर पर अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदत्त किए जाने का प्रावधान रखा गया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत इस दौरान अध्ययन हेतु स्कॉलर्स को यात्रा किराया, ट्यूशन फीस इत्यादि सहित सम्पूर्ण खर्चा राजस्थान की राज्य सरकार वहन करेगी।

इन विषयों में प्रवेश ले सकेंगें स्कॉलर्स

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत ह्यूमीनिटीज (मानविकी), सोशल साइंस (समाज विज्ञान) एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस (कृषि एवं वानिकी विज्ञान) नेचर एंड एनवायरमेंटल साइंस (प्रकृति एवं पर्यावरण विज्ञान), लॉ (विधि) विषयों के लिए 150, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (प्रबंधन एवं व्यवसाय प्रशासन) एवं इकोनमिक्स एंड फाइनेंस (अर्थशास्त्र एवं वित्त) के लिए 25 और प्योर साइंस एवं पब्लिक हेल्थ (विशुद्ध विज्ञान व जनस्वास्थ्य) विषयों के लिए 25 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाना प्रावधित है। उल्लेखनीय है कि इन विषयों में स्थान रिक्त रह जाने की दशा में इंजीनियरिंग एण्ड रिलेटेड साइंस (अभियांत्रिकी एवं सम्बद्ध विज्ञान) मेडिसिन तथा अप्लाइड साइंस (औषध एवं व्यावहारिक विज्ञान) विषयों में अधिकतम 15 उम्मीदवारों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

30 फीसदी अवार्ड महिला विद्यार्थी स्कॉलर्स के लिए आरक्षित

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत स्नातक स्तर के पाठक्रमों के लिए केवल मानविकी संकाय से सम्बंधित विषयों के अध्ययन के लिए ही छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रति वर्ष 200 मेधावी विद्यार्थियों में से 30 फीसदी अवार्ड महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर 60 छात्रा-स्कॉलर्स को विदेशी प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन की सुविधाएं सुलभ हो सकेगी। ज्ञातव्य रहे कि आवेदन से पूर्व आवेदकों का सम्बंधित विदेशी संस्थानों में प्रवेश होना जरूरी है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता से चयनित करने का प्रावधान रखा गया है।

आरजीएस पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन

आरजीएस पोर्टल पर आवेदन प्राप्त कर उम्मीदवारों का पोर्टल पर ही चयन किया जाता है। पात्र आवेदकों के 200 से अधिक आवेदन मिलने पर छात्रवृत्ति के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से संबंधित आवेदन एवं अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट पर www.hte.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। साथ ही किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए मेल आई.डी. rgs.cce@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पाली जिले में शिक्षा में नवाचार पर चर्चा करते हुए शिक्षक व अधिकारीगण

बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पाली में बढ़े कदम, नवाचार दे रहे हैं दिशा

डॉ. राजकमल पारीक
स्वतंत्र पत्रकार, पाली

- **शिक्षा को दे रहे हैं ऊंचाई खेल के साथ स्वच्छता व स्वास्थ्य पर ध्यान**
- **स्कूलों में शत प्रतिशत नामांकन की कवायद, स्वच्छता के लिए करेंगे प्रेरित**
- **सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को पारितोषिक देंगे, कार्मिक भी होंगे सम्मानित**
- **पाली में दो चरणों में योजना, पहला चरण शुरू**

राज्य सरकार की मंशा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पाली जिले में योजनाएं आकार लेने लग गई है। राज्य सरकार की ओर से संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और अन्य स्कूलों में बेहतर वातावरण के प्रयास रंग ला रहे हैं। बजट घोषणा अनुरुप बेटियों के सपनों की ऊंची उड़ान, बच्चों की बेहतर शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान में रुचि बढ़ाने, ओलम्पिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करने और स्वस्थ व स्वच्छ बालक-बालिकाओं की दिशा में कार्य करने के राज्य सरकार के इरादे धरातल पर सफल हो रहे हैं।

पाली जिले में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुरूप कई अभिनव प्रयोग शुरू किए हैं। विशेषकर बुनियादी शिक्षा की नींव ओर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्ता परक शिक्षा का माहौल बनाया जा सके। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बाद वहां सुविधाओं के विस्तार के साथ ही स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा का लाभ मिल पा रहा है।

वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद और स्वच्छता की एक पहल पाली जिला प्रशासन स्वच्छ विद्यालय-स्वस्थ विद्यालय की मुहिम भी शुरू की है। जिले में शिक्षा के साथ खेल से स्कूली विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास को लेकर नवाचार शुरू किया गया है। राज्य सरकार के स्कूलों में शत प्रतिशत नामांकन के निर्देशों के बाद अधिकाधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ने की कवायद को लेकर स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम नाम से नवाचार शुरू किया है। इसमें जिले के सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के साथ ही उनमें खेल भावना शुरुआत से ही विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने, उनमें अनुशासन व स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना है। प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम से विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्तर का विकास हो। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वच्छ सुंदर परिसर, स्वच्छ शौचालय, स्वयं की स्वच्छता के लिए समझा कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को नियमित अंतराल में पानी पीने की आदत डालने

के लिए घर से पानी की बोतल साथ लाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्रति दो पीरियड के बाद वाटर ब्रेक भी मिल रहा है। छात्रों में बढ़ती यूज एंड थ्रो की आदत को दूर करने के लिए पॉलीथिन व प्लास्टिक के विवेकपूर्ण निस्तारण व अन्य अनुपयोगी वेस्ट को बेस्ट मे बदलने की आदत का विकास करने व वेस्ट से विद्यालय का सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी आगामी चरण में होगा।

बनाएंगे स्कूलों में हेल्थ कार्ड

विद्यार्थियों का नियमित अंतराल में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाकर हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। एनीमिया मुक्त राजस्थान के अंतर्गत विद्यार्थियों को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां शिक्षकों की देखरेख में खिलाने, दृष्टि जांच करने व हाथ धोने की सही विधि की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियों का आयोजन इस कार्यक्रम के तहत समय-समय पर किया जा रहा है।

यह है कार्य योजना

पाली जिले में स्वच्छ विद्यालय-स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम का संचालन दो चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण की शुरुआत जिले में एक जुलाई से कर दी गई है जो कि 30 नवंबर तक जारी रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रथम चरण के विद्यालयों को चिन्हित करने के साथ ही कार्य शुरू कर दिया है। इसमें जिले के प्रत्येक ब्लॉक की 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतो के विद्यालय को लिया गया है। दूसरे चरण का संचालन एक दिसम्बर से 31 मार्च, 2023 तक किया जाएगा, इसमें प्रत्येक ब्लॉक की शेष ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को शामिल करेंगे।

श्रेष्ठ विद्यालयों को मिलेगा पारितोषिक

जिले में इस नवाचार के तहत होने वाले विभिन्न आयोजनों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। अच्छे कार्य करने पर पारितोषिक देकर प्रोत्साहन करेंगे। चयनित ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ 5 माध्यमिक व 5 प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर जिला स्तर पर पारितोषिक दिया जाएगा। जिला नवाचार निधि व भामाशाहों के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख व प्राथमिक विद्यालयों में 50 हजार की राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। जिला स्तर पर चयनित विद्यालय के अलावा ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यालयों का चयन कर प्रथम पुरस्कार 31 हजार, द्वितीय 21 हजार व तृतीय स्थान पर 11 हजार के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ कार्मिकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

गांधीजी के सपनों का स्कूल बनाने का प्रयास

महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य आदमी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए क्योंकि बुनियादी शिक्षा पर भविष्य की शिक्षा आधारित होती है। यही शिक्षा आदमी की नींव मजबूत करती है। गांधीजी स्वयं का कार्य स्वयं करने पर विश्वास रखते थे। इसी लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल प्रारंभ की है। गांधीजी की परिकल्पना के अनुसार विद्यार्थियों में स्व-अनुशासन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की भावना विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि विद्यार्थी गणवेश में आए, स्वयं के बैठने की जगह, कमरा व स्कूल परिसर स्वच्छ रखें, उन्हें पौधारोपण के लिए पौधे आवंटित कर रखरखाव का जिम्मा सौंपना, प्लास्टिक की बोतल व अन्य अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने की बजाय उनसे विद्यालय में सौन्दर्य की वस्तुएं बनाने की कला सिखाई जाएगी। ऐसा करने पर प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तहत इको फ्रेंडली पेन देंगे। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के साथ इस कार्यक्रम में पंचायतीराज, स्वास्थ्य, महिला अधिकारिता, जलदाय विभाग व आईसीडीएस का समन्वय भी रखा गया है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित की गई। जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण का क्रम भी तय हो गया है। फिलहाल प्रत्येक ब्लॉक के पांच मास्टर ट्रेनर को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया, अब वे प्रथम चरण के चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार की अवधारणा कि स्वच्छ माहौल में शिक्षण भी गुणवत्तापूर्ण बनें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनायता, पाली का खेल का मैदान

प्रतिदिन करेंगे चयन, आज स्वच्छ विद्यार्थी कौन ?

शिक्षा के साथ-साथ इस योजना में स्वच्छता व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों में स्वच्छता की भावना विकसित करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सबसे अच्छे छात्र-छात्राओं को टोपी-बैज देकर मनोबल बढाएंगे, नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिखकर भी प्रोत्साहित करेंगे। स्कूलों में नियमित रूप से स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन कर प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का हेल्थ कार्ड बनाएंगे। समय-समय पर उनकी आंखों, पेट व अन्य बीमारियों की जांच करवाई जाएगी, इसमें स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हेल्थ चेकअप होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हेल्थ प्रमोशन ग्रुप भी स्कूली स्तर पर गठित होंगे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्मित श्रीगंगानगर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

स्कूल शिक्षा रैंकिंग में श्रीगंगानगर अव्वल

लगातार दूसरे माह प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में गंगानगर रहा प्रथम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में समान रूप से सर्वांगीण विकास के लिये उल्लेखनीय कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों की राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समग्र रूप से किये जा रहे इन्हीं प्रयासों की बदौलत प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित हो रही हैं। शिक्षा विभाग के संदर्भ में देखें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिमाह जारी होने वाली शिक्षा रैंकिंग में श्रीगंगानगर जिला लगातार दूसरे माह अव्वल रहा है। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रैंकिंग में गंगानगर जिले ने मई व जून 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में इस उपलब्धि को बनाये रखने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिमाह जिला स्तरीय रैंकिंग जारी की जाती है। जून 2022 की रैंकिंग में गंगानगर जिले ने 200.82 अंक प्राप्त किये। 200.70 अंक लेकर चूरू दूसरे और 200.49 अंकों के साथ बूंदी जिला तीसरे स्थान पर रहा। इससे पूर्व मई 2022 की जिला स्तरीय रैंकिंग में 180.66 अंक लेकर गंगानगर जिला प्रथम स्थान पर रहा था। लगातार दूसरे माह प्रथम स्थान पर रहने की वजह से स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी प्रसन्नता का माहौल है।

अनिल कुमार शाक्य
जनसम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर

शिक्षा विभाग के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने 44 बिन्दुओं के आधार पर सभी सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन रैंकिंग तय होती है। जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ अन्य विभागीय कर्मचारियों की नियमित गतिविधियों, बैठकों और डेटा की ऑनलाईन फीडिंग की बदौलत लगातार दूसरे महीने गंगानगर जिले को प्रथम स्थान पर रहने का गौरव हासिल हुआ है। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग तय करने के लिये शाला दर्पण पोर्टल पर सभी स्कूलों को विद्यालय की श्रेणी, बेसिक प्रोफाइल, कर्मचारियों की संख्या, नामांकन की स्थिति, विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन, सुविधाएं, सेवा रिकॉर्ड, छात्रवृति योजना, भामाशाहों द्वारा दिये गये दान सहित कुल 44 बिन्दुओं की जानकारी देनी होती है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित श्रीगंगानगर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

जिले के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिये भी गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं। एक से लेकर 16 जुलाई तक जिले में विभिन्न गतिविधियां संचालित करते हुए नामांकन अभियान चलाया गया। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिये प्रवेश उत्सव कार्यक्रम दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। एक जुलाई से स्कूलों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रखी गई है।

विद्यार्थी परामर्श केन्द्र के मुताबिक सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों तथा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के साथ-साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में 3 से 18 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर समावेशी शिक्षा के तहत आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित किया जायेगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूलों की ओर से गांवों में प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जा रहा है। नामांकन बढ़ाने के लिये प्रत्येक पंचायत समिति और पालिका स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्था प्रधानों को उपखण्ड स्तर पर तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाले पांच संस्था प्रधान, शिक्षकों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले दो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिये किये जा रहे गंभीर प्रयासों की वजह से ही सुखद परिणाम मिल रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों द्वारा उल्लेखनीय अंक प्राप्त करते हुए अपने माता-पिता, स्कूल और जिले का नाम रोशन किया जा रहा है। उम्मीद है कि सफलता का यह क्रम भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा।

श्रीगंगानगर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 90 जी.बी.

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीगंगानगर

प्रदेश में प्रगति सोपान पर उच्च शिक्षा

शास्त्री कोसलेंद्रदास
सहायक आचार्य, ज.रा.रा.सं.वि.वि.जयपुर

प्राचीन भारत से लेकर आज तक शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान और कला संस्कृति के संरक्षण में जो भूमि सर्वाधिक उर्वर है, वह है राजस्थान की धरा। इस उत्कृष्ट धरती पर शताब्दियों पूर्व जन्मे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त (छठीं शताब्दी) और महाकवि माघ (सातवीं शताब्दी) जैसी विभूतियों ने व्यापक स्तर पर पूरे विश्व को आनुसंधानिक चिंतन से सम्मोहित एवं प्रभावित किया है। विद्या एवं ज्ञान विज्ञान की इस अमर परंपरा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अभिनव प्रयोग करते हुए शिक्षा की सर्वसुलभता और सर्वव्यापकता के लिए मजबूत प्रयास किए हैं। नए महाविद्यालय खोलने के साथ ही उच्च शिक्षा में बालिका शिक्षा की समृद्धि के लिए प्रदेश में ठोस कदम उठाए गए हैं। न केवल उच्च शिक्षा बल्कि संस्कृत शिक्षा, कृषि और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करते हुए इन्हें सामान्य विद्यार्थियों की पहुंच में लाने के सार्थक काम किए हैं।

नए महाविद्यालयों से उच्च अध्ययन का प्रकाश

सरकार ने विगत तीन वर्षों में 123 नए महाविद्यालय खोलकर सुदूर अंचलों में उच्च शिक्षा के उजियाले को फैलाने का महत्त्वपूर्ण काम किया है। सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राजधानी जयपुर के साथ ही संभाग स्तर के अतिरिक्त आदिवासी अंचल में ऐसे स्थानों पर महाविद्यालय खोले हैं, जिससे विद्यालयी शिक्षा के बाद विद्यार्थी के लिए उच्च शिक्षित होने के अवसर कम न हों। इस पवित्र उद्देश्य के साथ सरकार ने विगत तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2021-22) में 123 महाविद्यालय खोले हैं। खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों में भूमि आवंटन व भवन निर्माण की प्रक्रिया निर्बाध संचालित है। शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। नए महाविद्यालयों के लिए जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक भवन निर्माण हेतु राशि रुपए 175.97 करोड़ का बजट जारी किया गया है तथा 167.03 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

विद्या संबल योजना है कारगर

प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने आवश्यक समाधान करते हुए विद्या संबल योजना शुरू की। विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार ने इस योजना में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तहत लगभग 1100 शिक्षकों की भर्ती कर प्रदेश की उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की ओर ठोस कदम उठाया।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

महाविद्यालयों में भर्तियां

शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्थाई समाधान खोजा है। विभिन्न विषयों के 920 पदों के लिए भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इस भर्ती के उपरांत विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन करने के साथ ही शोध कार्य करने में सुविधा होगी।

कोरोना में नहीं रुका विद्यार्थियों का शिक्षण

कोरोना महामारी के काल में महाविद्यालयों में प्रवेश बारहवीं कक्षा के पर्सेंट के आधार पर दिए गए, जिससे प्रदेश के बच्चे बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, घर बैठे ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर सरकार ने नया कीर्तिस्तम्भ खड़ा किया है। शिक्षकों ने यूट्यूब एवं दूसरे चैनलों के माध्यम से पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को रिकॉर्ड कर छात्रों को सुलभ करवाया। इससे न केवल अध्ययन ही सुचारु संचालित हुआ बल्कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र की भी हानि नहीं हुई।

बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें

सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शिक्षा की प्राप्ति नि:शुल्क करना ऐतिहासिक कार्य है। उच्च शिक्षा में बेटियों की रुचि बढ़ाने से वे अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज का नेतृत्व कर सकेंगी। सरकार ने बेटियों की शारीरिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बड़ी पहल कर उनके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाई हैं, जिससे बेटियां आरोग्य प्राप्त कर सके।

मूकबधिर बच्चों के लिए महाविद्यालय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मूक एवं बधिर विद्यार्थियों की शारीरिक न्यूनता को समझकर उन्हें सबल बनाने के लिए स्वतंत्र मूकबधिक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इससे मूकबधिर बच्चों के लिए उच्च स्तरीय अध्ययन में सुविधा बढ़ेगी और वे अनुसंधान कार्य भी कर सकेंगे।

चार नए विश्वविद्यालय

प्रदेश में पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने के लिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है, जहां पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं में प्रवीण होकर विद्यार्थी अपना भविष्य संवार सकें। सरकार ने इस निमित्त राजधानी जयपुर में उद्देश्यपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना कर देश भर में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदेश को अत्युच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना होने से वहां सैंकड़ों विद्यार्थी पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार जयपुर में ही डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में विधि के अध्ययन को उत्कृष्टता प्राप्त हो रही है। बीकानेर में नया तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के साथ ही जोधपुर में इंजीनियरिंग अध्ययन के विस्तार के लिए एमबीएम विश्वविद्यालय खोला गया है।

सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 20 अगस्त, 2021 से शुरू की गई है। विदेश में अध्ययन हेतु प्रति वर्ष 200 अभ्यर्थियों को भेजे जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। योजना में मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान के विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कोटि संस्थानों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से छात्रवृति योजना को प्रारंभ किया गया है।

संस्कृत को सहारा

राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा में विद्यालय स्तर पर वर्षों से लंबित भर्तियां कर संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में भारी इजाफा किया है। प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में शिक्षकों के नियुक्त होने से संस्कृत अध्ययन की ओर छात्रों का रुझान बढ़ा है। संस्कृत महाविद्यालयों और जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ देकर सरकार ने संस्कृत शिक्षकों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। वर्षों से लंबित संस्कृत शिक्षा के सेवा नियमों को मंजूरी दी गई है। दौसा स्थित संस्कृत महाविद्यालय को शास्त्री से आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत कर वहां शिक्षकों के नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने अनेक रचनात्मक एवं प्रेरक संगोष्ठियों, समारोहों और कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रति आम लोगों की रुचि उत्पन्न करने के स्तुत्य प्रयास किए हैं।

प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

- बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
- गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
- जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
- राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
- राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनू
- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,जयपुर

- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
- राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
- डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
- एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर

उच्च शिक्षा में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

आयुक्तालय महाविद्यालय शिक्षा विभाग के अनुसार सत्र 2018-19 में राजकीय महाविद्यालयों में कुल छात्राओं की संख्या 2 लाख, 05 हजार, 234 थी जो कि कोविड-19 जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद सत्र 2021-22 में 2 लाख, 65 हजार, 238 हो गई है। प्रदेश में बालिका शिक्षा में यह बड़ी उपलब्धि है।

राज्य सरकार द्वारा खोले गये राजकीय महाविद्यालयों का विवरण

वर्ष	सहशिक्षा	कन्या	कुल
2019-20	29	11	40
2020-21	43	3	46
2021-22	18	19	37
2022-23	27	60	87
कुल	117	93	210

2019 से पूर्व कन्या महाविद्यालयों की संख्या महज 47 थी। सत्र 2019-20 में 11, सत्र 2020-21 में 03, सत्र 2021-22 में 19 एवं सत्र 2022-23 में 60 कन्या महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल 140 कन्या महाविद्यालय विस्तार पा चुके हैं। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह विस्तार कन्या महाविद्यालयों में अध्ययन कर रही छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहा है और प्रदेश की बालिकाओं को उच्च शिक्षार्जन में सुविधा हुई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में 29 राजकीय कृषि महाविद्यालय भी नये खोले हैं। वर्तमान में प्रदेश में 349 सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय, 140 कन्या महाविद्यालय और कुल 489 राजकीय महाविद्यालय प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संचालित है।

राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था

कल, आज और कल

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्राचीन समय से लेकर आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक पहुंचने में राजस्थान ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के उद्भव को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। शिक्षा और शिक्षण पद्धति की परंपरा भारत में वेदों और उपनिषदों के समय से देखी जा सकती है। विभिन्न धर्म शास्त्रों में तथा आर्यभट्ट, पाणिनी, कात्यायन, पतंजलि, सुश्रुत इत्यादि की पुस्तकों में शिक्षा व शिक्षण पद्धतियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

प्राचीन भारत में शिक्षण प्रणाली औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की थी, जिसे पाठशाला और गुरुकुल के माध्यम से सम्पादित किया जाता था। इसी प्रकार बिहार भी आध्यात्मिक उच्च शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के बेहतरीन केंद्र के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध थे। अन्य पुरातन शिक्षा केन्द्रों के रूप में विक्रमशीला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, उदयन्तपुरी विश्वविद्यालयएवं काशी विश्वविद्यालय प्रमुख हैं।

7 वीं से 12 वीं शताब्दी तक राजस्थान में शिक्षा का प्रारूप

राजस्थान में इस युग में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र भीनमाल था। जिसे उस समय 'श्रीमाल' कहा जाता था। इसी भीनमाल से माघ, माहुक, मंडन, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वानों का संबंध रहा है। शिक्षक व शिष्य का संबंध आत्मिक होता था। गुरुजन अपने शिष्यों को धार्मिक शिक्षा जैसे वेद, पुराण, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, साहित्य, संस्कृत व्याकरण के साथ-साथ राजनीति, प्रशासन, राजकाज, युद्धकला आदि से संबंधित विषय की शिक्षा प्रदान करते थे। इस काल में चूंकि शिक्षा नि:शुल्क थी, अत: शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था शासक और सरकार का कार्य था। शासक व जनता दोनों शिक्षकों को भरण पोषण के लिए दान एवं अन्य उपहार देते थे।

इस समय शिक्षा प्रणाली प्रायः मौखिक होती थी, अत: वाद विवाद और विचार-विनिमय को प्रमुखता दी जाती थी। जैन साहित्यकार रवि प्रभु श्री की धर्म घोष स्तुति से पता चलता है कि चौहान शासक अजयपाल ने धर्मघोष व गुण चंद्र के बीच होने वाले वाद-विवाद की अध्यक्षता की थी। इस युग में शिक्षकों को आचार्य, पंडित, उपाध्याय, भट्ट, कविप्रवर, गुरुदेव आदि नामों से जाना जाता था। तत्कालीन समाज में इनका मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा खूब थी।

12वीं से 18 वीं शताब्दी तक राजस्थान में शिक्षा

इस युग में शिक्षा हेतु गुरुकुल, मठ, मंदिर, जैन उपासरे तथा प्राथमिक पाठशाला भी थी, जहां बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। राज्य की ओर से इन संस्थाओं को आर्थिक मदद व भूमि अनुदान दिया जाता था। उस भूमि की उपज से यह संस्थान चलते थे। यहां पर शिक्षा के प्रमुख विषय के रूप में वेदशास्त्र, नीतिशास्त्र, मीमांसा, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण, ज्योतिषशास्त्र, गणित, साहित्य, संस्कृत आदि पढ़ते थे। यहां पर पढ़ाने वाले उच्च शिक्षित लोगों को विद्वान, पंडित, उपाध्याय, महामहोपाध्याय, आचार्य आदि सम्मानजनक उपाधियों से नवाजा जाता था। ज्ञानी जन को शासक वर्ग सम्मान भी देता था। इसके साथ ही साथ बालक अपनी प्रारंभिक तथा व्यवसायिक कौशल की शिक्षा अपने पैतृक व्यवसाय से भी सीखता था।

कुशल दस्तकार व शिल्पकार खेती तथा वाणिज्य संबंधी शिक्षा

आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषाहार ग्रहण करते हुए बच्चे

बालक अपने घर से ही सीखता था। इस युग में स्त्रियों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। स्त्रियां अधिकांश नृत्य, संगीत, चित्रकला व चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण करती थी, परंतु शिक्षित स्त्रियों की संख्या काफी कम थी। अधिकांशत: उन्हें घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय स्त्रियों के लिए औपचारिक शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था। उन्हें अनौपचारिक रूप से घर पर ही रख कर शिक्षा दी जाती थी। 18 वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही प्रचलित रही। जिसमें शिक्षकों को खर्च हेतु अनुदान की व्यवस्था करने का कार्य राज्य का होता था।

इस काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा फारसी भाषा थी। विद्वान जन राजा का सहयोग पाते थे एवं राजा भी इन्हें हर संभव मदद प्रदान करते थे। यही कारण है कि इस काल का चारण साहित्य अति प्रसिद्ध है एवं उस काल के इतिहास को जानने में सर्वाधिक मददगार है। इसी काल में जोधपुर के साहित्यकार मुहणोत नैणसी द्वारा लिखित पुस्तक 'मारवाड़ रा परगना री विगत वार' को 'राजस्थान का गजेटियर' माना जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम उस काल की संस्कृति, रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था आदि के बारे में सरलता से जान सकते हैं। राजस्थान में शिक्षा, कला, संस्कृति व साहित्य आदि के विकास में राजाओं का योगदान काफी रहा है। वर्तमान में हम जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें देखते हैं, यह उसी काल की कला, संस्कृति व शिक्षा का हमें ज्ञान करवाते हैं।

ब्रिटिश काल में शिक्षा का परिदृश्य

ब्रिटिश दस्तावेजों में वर्ष1818 से पूर्व शिक्षा पद्धति को देशी शिक्षा (इंडीजीनस एजुकेशन) के नाम से संबोधित किया गया है। राजकीय अभिलेखागार में जनानी ड्योढी तहरीर नाम से एक संग्रह है जिससे पता चलता है कि राज परिवारों से संबंधित महिलाएं सांस्कृतिक मूल्यों और सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण लेती थीं। अनेक विदुषी चारण महिलाएं और कुलीन वर्ग की महिलाओं में शिक्षा का प्रचलन था। जैन महिला साध्वियों को उपासरा में भाषा साहित्य एवं अनुवाद से संबंधित शिक्षा दी जाती थी।

ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में स्कूल शिक्षा तीन वर्गों में विभक्त थी - 1. प्राथमिक स्कूल 2. मिडिल स्कूल एवं 3. हाई स्कूल। प्राथमिक स्कूल वर्नाकुलर स्कूल थे जबकि ग्रामीण और तहसील स्तर पर वर्नाकुलर मिडिल स्कूलों का उल्लेख किया गया है। दूसरे स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल थे इसमें एक मिडिल स्कूल और दूसरे हाई स्कूल हुआ करते थे। इसी प्रकार 1819 में रेजिडेंट अक्टरलोनी के निर्देश पर जेवन कैरी ने पहले अजमेर में और बाद में पुष्कर, भिनाय और केकड़ी में अंग्रेजी भाषा के स्कूल खुले। लेकिन 1913 में जनता के विरोध के कारण यह स्कूल बंद करने पड़े।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी। अजमेर में 1836 में पहला सरकारी स्कूल खोला गया जो 1868 में इंटरमीडिएट तथा 1869 में स्नातक कॉलेज बना। राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर महाराजा बन्नेसिंह की प्रेरणा से पंडित रूपनारायण ने 1842 में और उसके बाद इसी साल भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने आधुनिक स्कूलों की शुरुआत की।

प्राचीन शिक्षा नगरी भीनमाल को कहा जाता था जो वर्तमान में जालौर जिले में है। राजस्थान में सर्वप्रथम आधुनिक अंग्रेजी स्कूल 1842 में अलवर एवं भरतपुर में स्थापित हुए। अंग्रेजी शिक्षा हेतु लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की।

आधुनिक राजस्थान में शिक्षा की अलख

स्वतंत्रता सेनानी हरीभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के निकट हटून्डी गांव में महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की। जयपुर के शासक रामसिंह ने 1844 में जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की जो वर्तमान में महाराजा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय कहा जाता है, की स्थापना 1947 में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से 1898 में अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। हीरालाल शास्त्री जी ने 1953 में टोंक में जीवन शिक्षा कुटीर नाम से महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

पुस्तकालय में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी

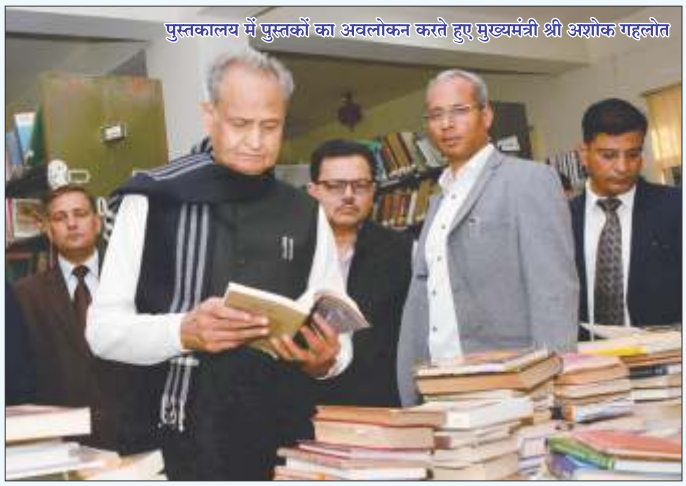
पुस्तकालय में पुस्तकों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

महिला शिक्षा को प्रोत्साहन

देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रथम कदम जयपुर महाराजा रामसिंह ने 7 मई 1866 को कांति चंद्र मुखर्जी के परामर्श पर कन्या विद्यालय स्थापित करके किया। यहां छात्राओं को सिलाई भी सिखाई जाती थी। इसी साल भरतपुर और उदयपुर में फिर अलवर व कोटा (1872 में) तथा 1883 में झालावाड़ में कन्या स्कूल खोले गए। जोधपुर में हेवसन कन्या विद्यालय 1886 में स्थापित किया गया। टोंक रियासत में 1885 में मुस्लिम कन्याओं के लिए और 1888 बीकानेर में लेडी एलीगन की यात्रा के समय कन्या विद्यालय खोले गए।

नसीराबाद में सन 1861 में ईसाई मिशनरी के प्रयासों से प्रथम गर्ल्स वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किया गया। यह राजपूताना का प्रथम स्कूल था जहां गर्ल्स स्काउट गाइड प्रारंभ की गई। इसी प्रकार सन् 1866 में पुष्कर में मिशनरी विलेज स्कूल प्रारंभ हुआ। दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और शेखावाटी में आर्य समाज के विद्यालयों की स्थापना की।

अंग्रेजी विद्यालयों का संचालन

अजमेर में 1913 में स्थापित सावित्री कॉलेज और उदयपुर का महिला महाविद्यालय आर्य समाज से प्रेरित थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा पहाड़ी लोगों को शिक्षित करने के लिए दिसंबर 1863 में टॉडगढ़ में रॉवर्स स्कूल स्थापित किया गया। इसी प्रकार अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, कोटा, अलवर और बांदीकुई में मिशनरी स्कूल खोले गए।

रियासत काल में राजस्थान में हिंदू पाठशाला एवं मुस्लिम मकतब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। किन्तु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के उदय के साथ ही आधुनिक अंग्रेजी स्कूल भी राजस्थान में शुरू हुए। लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर सर्वप्रथम अलवर एवं भरतपुर में 1842 में अंग्रेजी विद्यालय प्रारंभ हुए। सन् 1844 में जयपुर एवं 1863 में उदयपुर रियासत में भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना हुई। 19वीं सदी के मध्य तक राजस्थान में तीन प्रकार की कुल 647 शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हुआ करती थी।

शिक्षा बोर्ड की स्थापना

शिक्षा बोर्ड के रूप में राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जयपुर के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी श्री के.पी. किचलू को नियुक्त किया गया।

राजस्थान में मारवाड़ी धनाढ्य वर्ग द्वारा शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। शेखावाटी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट एवं मोदी एजुकेशन ट्रस्ट ने कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। बगड, फ़तेहपुर, रामगढ़, नवलगढ़, लाडनूं, सीकर इत्यादि स्थानों पर शिक्षा के अनेक संस्थान स्थापित हुए। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी भामाशाहों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

शिक्षक शिक्षण संस्थाएं

शिक्षक शिक्षण संस्थाओं के रूप में सर्वप्रथम विद्या भवन एजुकेशन सोसाइटी ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1941 में प्रारंभ किया जबकि दूसरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज राजपूताना मध्य भारत और ग्वालियर संयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष श्री जे.सी. चटर्जी के प्रयासों से अजमेर में 1941 में ही खोला गया। तीसरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1946 में बीकानेर में खुला। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज उदयपुर में 1933 में प्रारंभ हुआ, इसे आयुर्वेद मंडल कानपुर से संबंधित किया गया।

विधि शिक्षा

विधि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम भूपाल नोबल्स कॉलेज उदयपुर में 1946 में एलएल बी की कक्षाएं प्रारंभ की गई, उसके बाद लॉ कॉलेज जयपुर, जसवंत कॉलेज जोधपुर, राज ऋषि कॉलेज अलवर और डूंगर कॉलेज बीकानेर में विधि के अध्ययन की व्यवस्था की गई थी। आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। अभी हाल ही में सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की जा रही है।

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, विद्याधर नगर

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय विद्याधर नगर

रा.उ.मा.विद्यालय, चांदसेन, टोंक

फोटो फीचर

राजकीय विद्यालयों की बदली तस्वीर

शैक्षणिक विकास के चलते अध्ययन-अध्यापन के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रदेश के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के भवनों की सूरत बदल रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु निजी शिक्षण संस्थानों से भी अधिक होड़ मची हुई है, जो निश्चित रूप से प्रदेश के उत्तरोत्तर शैक्षणिक विकास की द्योतक है। प्रस्तुत है प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों की तस्वीर।

छाया चित्र: लक्ष्मण पारंगी, अशोक गुरावा, हरिशंकर शर्मा

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

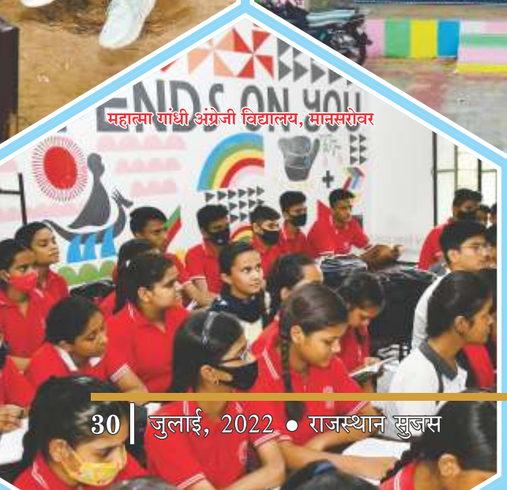

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मानसरोवर

रा.उ.मा.विद्यालय, चांदसेन, टोंक

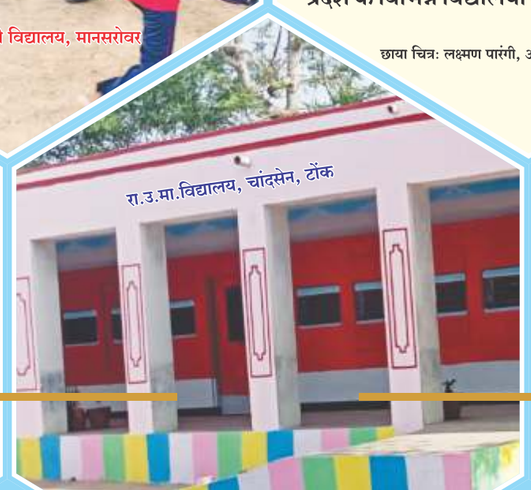

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय मानसरोवर

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
उप निदेशक, जनसम्पर्क

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की रणनीति बनाई जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में युवा वर्ग

राज्य सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में युवा वर्ग है। सरकार का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर समर्पित होगा। इसमें युवा केंद्रित योजनाओं, रोजगार की उपलब्धताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्किल यूनिवर्सिटी का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या और क्षमता में वृद्धि की गई है। प्रदेश में स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई है, अब उसके कार्य को और विस्तार दिया जा रहा है।

प्रदेश में देशी-विदेशी कंपनियों के स्थापित होने से बढ़ीं रोजगार की संभावनाएं

राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाकर देशी-विदेशी कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कौशल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण को अधिक मजबूत और वर्तमान मांग के अनुसार करने की आवश्यकता प्रतिपारित की है। इससे एक ऐसा सेटअप तैयार होगा, जहां पर युवाओं को रोजगार के साथ करिअर गाइडेंस एक कॉल पर मिल सकें।

नीमराना में जापान की कंपनियों द्वारा स्किल सेंटर में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ऐसी कई कंपनियां भी राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक 1.25 लाख नौकरियां दे दी गई हैं। एक लाख प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद मायाराम द्वारा राजस्थान में रोजगार की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश की है।

भर्ती परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु मॉडल का किया जाएगा अध्ययन

राज्य में भर्ती परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु राज्यों की भर्ती परीक्षा के मॉडल का अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय टीम दोनों राज्यों में जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगी। इसके बाद राजस्थान में भी उसी पैटर्न पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने पर विचार किया जाएगा। भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधारात्मक सुझाव देने के लिए गठित जस्टिस व्यास समिति ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को प्रस्तुत की। राज्य सरकार युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्तियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाएं गोपनीयता के साथ आयोजित कराई जा रही हैं।

भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधारात्मक सुझाव देने के लिए गठित जस्टिस व्यास समिति के सदस्य मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

भर्ती परीक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया में विश्वसनीयता बनाने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाऐंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 30 जनवरी 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन गया था। इसमें सेवानिवृत्त आईपीएस एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एम.एल. कुमावत को सदस्य और कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। इस समिति द्वारा महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल स्थित भर्ती परीक्षाओं के आयोग, बोर्ड, संस्थाओं के साथ आरपीएससी, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर, प्रिंटिंग, वितरण, परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने के लिए आधारभूत संरचना, सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी मापदंड, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परीक्षा केंद्र अधीक्षक, परीक्षा के लिए जिला समन्वयक, सुपरवाइजर एवं वीक्षक की भूमिका एवं दायित्वों, कोताही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई, उत्तरपुस्तिकाओं के लिए परिवहन व्यवस्था संबंधित कई सुझाव दिए हैं।

किसान अब किसी भी अधिकृत डीलर से अनुदान पर खरीद सकेगा कृषि आदान : मोल-भाव भी कर सकेगा

राज्य के किसान अब अपनी इच्छानुसार किसी भी अधिकृत अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से अनुदान पर किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान खरीद सकता है। कृषक अधिकृत डीलरों से स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल-भाव भी कर सकेगा।

कृषकों की सुविधा के लिए यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पूर्व काश्तकार केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ही पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स तथा सूक्ष्म पोषक तत्व खरीद सकता था। इसके अतिरिक्त कृषि आदानों की रेट भी विभाग द्वारा ही तय की जाती थी। अब किसी भी अधिकृत अनुज्ञापत्रधारी डीलर से किसान अपने गांव में ही तथा मोल-भाव करके सही कीमत पर कृषि आदानों की खरीद कर सकेगा।

यदि कोई कृषक कृषि आदानों की खरीद पर अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जायेगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है।

पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टेयर देय होगा। बायो फर्टिलाइजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपये प्रति हैक्टेयर मिलेगा। प्रति कृषक अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर होगी।

पशु चिकित्सा शिक्षा के इंटर्न को मिलेगा स्टाईफण्ड पर महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पशु चिकित्सा शिक्षा के इंटर्न छात्रों को देय स्टाईफण्ड पर आयुर्वेद एवं मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वेटेरिनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईफण्ड के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा ऐलोपैथी तथा आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाईपेण्ड पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पशु चिकित्सा शिक्षा के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाईफण्ड के साथ महंगाई भत्ता 1 अप्रेल, 2022 से मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेटेरिनरी इंटर्न छात्रों को देय स्टाईफण्ड 3500 रुपये

से बढ़ाकर 14000 रुपये करने के आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

राज्य सरकार का 7.5 लाख कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर बोनस का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।

बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रुपये प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।

शहरी जल प्रदाय योजना नोहर के संवर्धन कार्य के लिए 16.98 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शहरी जल प्रदाय योजना नोहर (हनुमानगढ़) के संवर्धन कार्य के लिए 16.98 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से नहरबंदी के समय पानी की मांग को पूरा करने के लिए रॉ वाटर स्टोरेज क्षमता 7 दिन से बढ़कर 30 दिन हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि यह परियोजना सतही जल पर आधारित है एवं इसका जल स्रोत इन्दिरा गांधी नहर से है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत राशि में 5 वर्ष की संचालन एवं संधारण राशि सम्मिलित है। इससे नोहर शहर और आसपास के 8 गांवों में पानी की उपलब्धता हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की वित्तीय स्वीकृति से संवर्धन कार्य यथासमय पूर्ण हो सकेंगे तथा आमजन को राहत मिलेगी।

प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16.50 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रस्ताव के अनुसार गिर्वा (उदयपुर), केरू (जोधपुर), हिण्डौन (करौली), धोद (सीकर), परबतसर (नागौर), परसरामपुरा (झुंझुनूं), बानसूर (अलवर), रूपवास (भरतपुर), उच्चैन (भरतपुर), तारानगर (चूरू) तथा बगरू (जयपुर) में नए खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम (आरएसआरडीसी) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से नए बनने वाले सभी खेल स्टेडियमों में 200 मीटर का सिंडर एथेलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो-खो व कबड्डी के मैदान आदि खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, ढ़ांचागत सुविधाओं के रूप में स्टेडियम कार्यालय की बिल्डिंग, टॉयलेट ब्लॉक, ट्यूबवेल, आन्तरिक सड़कें व चारदीवारी आदि का निर्माण भी होगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए खेल स्टेडियमों का निर्माण करने की घोषणा की थी।

शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास

शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना से बीकानेर शहर और आसपास के 32 गांवों के लगभग 13 लाख लोगों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा।

शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना बीकानेर के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना बीकानेर का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जलप्रदाय योजना का शिलान्यास किया। यह योजना बीकानेर के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगी। इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान के लोग पानी का मोल समझते हैं तथा इसका प्रभावी प्रबंधन करते आए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन है।

देश में 10 प्रतिशत भू-भाग वाले राजस्थान में सिर्फ 1 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है। ऐसे में इसका प्रभावी प्रबंधन बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा घर-घर पानी पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के 45 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य आने लगा है। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है।

राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने को संकल्पबद्ध है। सरकार के जनकल्याणकारी निर्णयों से प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। मनरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बीकानेर शहर की वर्ष 2052 तक की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। योजना के मास्टर प्लान के अनुसार प्रथम चरण में 614.9 करोड़ तथा दूसरे चरण में 798 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाएंगे।

जलप्रदाय योजना के प्रथम पैकेज के लिए 176 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत चकगर्बी में 30 हजार लाख लीटर व बीछवाल में 25 हजार लाख लीटर क्षमता के रॉ वाटर जलाशय तथा दोनों स्थानों पर 300 लाख लीटर क्षमता के जल शोधन यंत्र स्थापित किए जाएंगे। द्वितीय पैकेज में 15 उच्च जलाशय, 2 स्वच्छ जलाशय तथा 61 हजार से अधिक कनेक्शन दिए जाएंगे। पहला फेज नवंबर 2023 तथा दूसरा मई 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरू वशिष्ठ पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये

राज्य सरकार प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रोत्साहन दे रही है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करने और खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने में संकल्पित सरकार द्वारा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है।

अब महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को 5-5 लाख रुपये पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन में पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरू वशिष्ठ पुरस्कार तथा 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी तक इन पुरस्कारों में विजेताओं को एक-एक लाख रूपये की राशि से सम्मानित किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 मई, 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम में लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।

वर्ष 2014 में बढ़े 50 हजार रुपये, अब पांच गुना बढ़ोतरी

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ

प्रशासन शहरों के संग का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

पुरस्कार की राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अहम फैसले से पुरस्कार राशि में अब पांच गुना बढ़ोतरी हो गई है।

अभी तक 210 खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार

गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1985-86 में की गई थी अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है।

229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्तियां देने का भी निर्णय लिया गया। इसमें अभी तक 229 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी है।

प्रदेश के 35 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कृषि संकाय

प्रदेश के 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। इससे 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को कृषि की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि संकाय खोले जाने और प्रत्येक विद्यालय में 1-1 व्याख्याता कृषि का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है।

पट्टे जारी करने के लिए विशेष अभियान

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने बिना पट्टे वाले घरों के नियमन में काफी रियायतें दी हैं ताकि 15 जुलाई से शुरू हुए वार्डवार शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सके। पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85 प्रतिशत तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तातंरित करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके।

पट्टे जारी करने के लिए सरकार दे रही विशेष शिथिलताएं

कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनीयों को 70:30 अनुपात में रखकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भू-खण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। साथ ही, कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को पट्टा मिल सके। जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने पर पाबंदी थी, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों की घनी आबादी में बने हुए पुराने मकानों का 501 रुपये में पट्टा देने के लिए धारा 69-ए में काफी शिथिलताएं दी गई हैं।

सांगीतिक परम्परा से समृद्ध धरा: मरुधरा

डॉ. वन्दना खुराना
सहायक आचार्य कंठसंगीत, राजस्थान संगीत संस्थान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सन् 2022 के बजट में घोषित नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर में स्नातक स्तर पर संगीत को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित कर संगीत कला के भविष्य को सुरक्षित कर समाज को एक अमूल्य उपहार दिया है।

मनुष्य पैदा होता है, किन्तु मनुष्यता अर्जित की जाती है। कृतित्व और आचरण से इस प्रक्रिया में जिस क्षण मूल्य चेतना का उदय होता है, उसी क्षण संस्कृति का आर्विभाव भी। डॉ. हरद्वारी लाल शर्मा की यह पंक्तियाँ प्रमाणित करती हैं कि कला संस्कृति की जननी भी है और कला से ही संस्कृति का विकास होता है। किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, अत: जितनी उत्कृष्ट एवं विकसित संस्कृति होती है, उतना ही वह समाज उच्चकोटि का माना जाता है।

कला मानव मन की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम सिद्ध होती है। कला का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। कला और संस्कृति एक ही वृक्ष की दो शाखा जैसी हैं। कला और जीवन में भी घनिष्ठ संबंध है। कला में ऐसी शक्ति होती है जो मानव को संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर ऐसे उच्च स्थान पर ले जाती है जहाँ मनुष्य न केवल मनुष्य रह जाता है अपितु उसका सीधा साक्षात्कार उस कलाविज्ञ से हो जाता है, जहां से उसकी कला आकार लेती है। कला व्यक्ति के मन से स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र व भाषा आदि की सीमाओं को तोड़कर उसे मुक्त आकाश देती है। व्यक्ति के मन को उदार बनाती है तथा व्यक्ति को 'स्व' से निकालकर 'वसुधैवकुटुम्बकम्' से जोड़ देती है।

भारतीय संस्कृति के निर्माताओं ने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जीवन में कलाओं के महत्त्व को स्वीकारा है। महर्षि वात्स्यायन ने चौसठ कलाओं की शिक्षा प्राप्त करना जीवन में आवश्यक माना है। उन चौसठ कलाओं में संगीत को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसका एक कारण यह है कि भारतीय संगीत कला मनोरंजन का साधन तो है किन्तु वह मनोरंजन ऐसा होता है कि जिससे मानव का नैतिक स्तर गिरता नहीं बल्कि उसका नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक विकास भी होता जाता है। अर्थात् संगीत के माध्यम से मानव जीवन के समस्त पक्षों का विकास होता है। भारतीय ज्ञान परम्परा एवं चिंतन-दर्शन में विद्वानों ने संगीत कला को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरूषार्थो की प्राप्ति का साधन माना है। संगीत से आनंद की सृष्टि होती है और यह आनंद आध्यात्मिक है।

भारतीय संगीत ने जीवन के सदैव उच्च आदर्श का दृष्टिकोण रखकर जीवन के विकास का पथ सदैव प्रशस्त किया है और मानवता, प्रेम, और सद्भाव को विकसित करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि जीवन को संगीतमय बनाने का अर्थ है उसे एकरस बनाना तथा मनुष्य की पाशविक वृत्तियों के शमन व शोधन हेतु जीवन में संगीत की उपस्थिति अनिवार्य है। संगीत एक कला है और कला का कार्य व्यक्ति एवं समाज को समीप लाना है। इसी कार्य के लिए संसार में भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें से 'कला' भी एक है। विश्वभाषा के रूप में संगीत को हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य स्थान प्राप्त है। संगीत कला ने मानवीय गुणों की वृद्धि में अमूल्य योगदान दिया है। संगीतकला के इस अमूल्य योगदान को स्वीकारते हुए भारतीय समाज ने संगीत कला को अपना अभिन्न अंग बनाया है। संगीतकला को जीवित रखने के लिये आवश्यक है पुरानी पीढ़ी द्वारा नवीन पीढ़ी को इसकी शिक्षा प्रदान करना। भारतीय समाज में संगीत शिक्षा न केवल गुरू-शिष्य परम्परा एवं घराना-पद्धति द्वारा दी जाती रही है बल्कि इसे आमजन हेतु सुलभ बनाकर संस्थागत शिक्षण पद्धति के रूप में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर प्रदत्त किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य में तो सांगीतिक-परम्परा का समृद्धशाली इतिहास रहा है। यहां लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत दोनों ही धाराओं के रूप में संगीत कला समस्त समाज में प्रवाहमान रही है। जहां एक ओर सांगीतिक जातियों परिवारों ने लोकसंगीत एवं घराना पद्धति को संभाला हुआ है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर संगीत को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित कर इसकी विधिवत शिक्षा दे कर समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। राजस्थान सरकार संगीतकला के उत्थान में पूर्णत: प्रयत्नशील है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सन् 2022 के बजट में घोषित नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर में स्नातक स्तर पर संगीत को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित कर संगीत कला के भविष्य को सुरक्षित कर समाज को एक अमूल्य उपहार दिया है।

राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सिरोही

धरातल पर क्रियान्विति

सुश्री हेमलता सिसोदिया
जनसम्पर्क अधिकारी, सिरोही

भारत विश्व पटल पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय वैश्वीकरण (Globlisation) का दौर है। ऐसे में शिक्षा के सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ सरेखन (Alignment with Global sustainable development goals) करने के लिए वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा में सतत प्रयास करने की महत्ती आवश्यकता है। जिसके लिए बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ सरेखन कर अपना भविष्य तलाश सकें।

राजस्थान हिन्दी भाषी प्रदेश होने से प्राय: देखा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आम नागरिकों के बच्चों के लिए निजी विद्यालय एक स्वप्न ही है। वे उन विद्यालयों को दूर से देख सकते है लेकिन उन विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस इतनी ऊंची होती है कि सामान्य बालक और विशेषकर गरीब बच्चे ऐसे विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आरटीई के तहत कुछ प्रतिशत आरक्षण तय कर निजी विद्यालयों को निर्देशित भी किया कि वे अपने विद्यालयों में गरीब बच्चों को भी प्रवेश दें लेकिन इससे ज्यादा लक्ष्य अर्जित नहीं हो सका।

ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)'' कक्षा 1 से 12 तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमें सहशिक्षण (Co-Education) की व्यवस्था की गई है ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाएं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

राज्य सरकार ने इस महत्ती योजना की शुरूआत जून 2019 में की एवं राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना की। इस तरह राज्य में कुल 33 विद्यालयों की शुरुआत जुलाई 2019 से हुई।

हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयो में बच्चों को न केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है वरन् सह शैक्षिक गतिविधियों में भी उन्हे दक्ष किया जा रहा है। सिरोही शहर के महात्मा गांधी विद्यालय के बच्चे (गायन दल) भारत की कुल 15 एवं 5 विदेशी भाषाओं में गायन प्रस्तुत करने में दक्ष हैं और इसी उपलब्धि को देखते हुए इस विद्यालय के एक छात्र कृश खंडेलवाल (Best Student of the Year) कक्षा 10 और एक छात्रा सुश्री वैदेही शर्मा (School Topper with 97% Marks) को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि महात्मा गांधी विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जावें।

भौतिक संरचनाओं में चयनित विद्यालय का भवन ही ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)'' का भवन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा-कक्षों की गतिविधि आधारित शिक्षण कक्षों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा। उपलब्ध संसाधनों की कमी की स्थिति में प्राथमिकता से कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल सुविधा बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, एबीएल कक्षाकक्ष, नेट कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता, स्मार्ट क्लास, गणित विज्ञान कक्ष आदि की उपलब्धता चरणबद्ध रूप से की जायेगी ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें। ●

एजुकेशन सिटी: अजमेर

पौने दो सौ साल पुराना है आधुनिक शिक्षा का इतिहास

भानु प्रताप सिंह गुर्जर
जनसम्पर्क अधिकारी, अजमेर

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

देश के शिक्षा जगत में अजमेर अग्रणी शहरों में शामिल है। पौने दो सौ सालों से भी ज्यादा समय से यह सफर अनवरत जारी है। देश के शैक्षिक क्षितिज में मेयो कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राजकीय महाविद्यालय, डीएवी कॉलेज और क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान मौजूद हैं।

आजादी के समय अजमेर में शिक्षण संस्थाएं

आजादी के समय सन् 1947 में अजमेर राज्य में 380 शिक्षण संस्थाएं थीं। इनमें एक स्नातक महाविद्यालय, 4 इंटर कॉलेज, 23 हाई स्कूल, 48 मिडिल स्कूल और 307 प्राइमरी स्कूल थे। सन् 1947 से लेकर 1952 में लोकतांत्रिक सरकार के गठन तक शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 688 हो गई। राज्य पुनर्गठन से पूर्व अजमेर स्टेट की सरकार ने भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में समाज शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गई। सन् 1956 में राजस्थान में विलय के समय अजमेर ऐसा पहला राज्य था, जहां अनिवार्य शिक्षा कानून लागू था।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय देश के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। इसकी स्थापना सन् 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पब्लिक स्कूल के रूप में की थी। सन 1847 में इसे क्रमोन्नत कर हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। 1896 में इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कर महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। यहां कला स्नातक की शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद 1913 में विज्ञान स्नातक की भी पढ़ाई शुरू की गई। सन् 1927 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। सन् 1946 में यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना। वाणिज्य स्नातक और विधि स्नातक की कक्षाएं क्रमश: 1949 व 1951 में जाकर शुरू हो पाई। वर्तमान में यह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

मेयो कॉलेज

मेयो कॉलेज देश के सबसे पुराने पब्लिक बोर्डिंग स्कूल में शामिल है। वर्ष 1875 में इसकी स्थापना की गई। स्कूल की शुरुआत अक्टूबर, 1875 में प्राचार्य सर ऑलिवर सेंट जोन और एक विद्यार्थी के साथ हुई जो अलवर के महाराजा मंगलसिंह थे। मेयो कॉलेज की पहचान दुनिया के श्रेष्ठ स्कूलों के रूप में है। मेयो कॉलेज के पास ही मेयो गर्ल्स स्कूल संचालित किया जा रहा है। यह भी बालिका शिक्षा में देश का अग्रणी स्कूल है।

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन

केन्द्र सरकार ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की स्थापना की थी। इसी सोच के साथ वर्ष 1963 में केन्द्र सरकार ने अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में रीजनल कॉलेजों की स्थापना की। वर्ष 1995 में इसे क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान (रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन) का नाम दिया गया। वर्तमान में यह उत्तर भारत के शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्यरत है।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर

देश में सिर्फ पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। उनमें से एक अजमेर में स्थित है। वर्ष 1930 में इसकी स्थापना किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में की गई थी। उस समय इसमें सिर्फ सेना कार्मिकों के बेटों को प्रवेश दिया जाता था। स्कूल के पहले विद्यार्थी के रूप में 15 नवम्बर, 1930 को रोल नम्बर एक पर अनवर अली खान पुत्र श्री नवाब अली खान को नामांकित किया गया। वर्ष 1952 में स्कूल सेना के साथ ही आम आदमियों के बेटों को भी प्रवेश के लिए खोल दिया गया। वर्ष 1966 में इसे मिलिट्री स्कूल और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया। देश के अन्य चार मिलिट्री स्कूल चैल (शिमला), धौलपुर (राजस्थान) तथा बैंगलुरू व बेलगाम (कर्नाटक) में स्थित हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान

केन्द्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ के पास जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 3 मार्च 2009 को की गई। यह उच्च शिक्षा के प्रमुख स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना एक अगस्त 1987 को की गई थी। राजस्थान विवि के क्षेत्राधिकार से कुछ जिलों को हटाकर अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। वर्ष 1996 में विश्वविद्यालय का नामकरण महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम किया गया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर

उदयपुर का अनूठा राजकीय विद्यालय

राउमावि वरड़ा : यहां दीवारें भी पढ़ाती हैं बच्चों को

राज्य सरकार इन दिनों विद्यालयों में स्तरीय साधन सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, इन्ही स्थितियों के बीच उदयपुर जिले का एक स्कूल ऐसा भी है जो भामाशाहों के सहयोग से उच्च स्तरीय वातावरण उपलब्ध करा रहा है। यह स्कूल है उदयपुर जिला मुख्यालय के समीप ही बड़गांव ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर का कक्षा कक्ष

डॉ. कमलेश शर्मा
उपनिदेशक, जनसंपर्क, उदयपुर

बिना पलस्तर की दीवारें भी बोलती है

इस स्कूल में हाल ही में बनाया गया एक नवीन भवन बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है। पूरे भवन को स्थानीय पत्थरों की चुनाई से बनाया गया है। इस पूरे भवन पर पलस्तर न करते हुए पत्थरों को आकर्षक ढंग से पॉलिश करते हुए सजाया गया है जिससे यह हेरिटेज शैली का भवन दिखाई देता है। पूरी तरह से कलात्मक तरीके से बनाया गया यह भवन विद्यार्थियों के लिए बड़े आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि इस भवन की दीवारों पर विद्यार्थियों के लिए कई उपयोगी बातों को उकेरा गया है। इन दीवारों पर विभिन्न प्रतीक, सैन्य प्रतीकों के साथ-साथ वाद्य यंत्रों, नोबल पुरस्कार, वैज्ञानिक, विश्व विरासतों के आकर्षक रंगीन चित्रों को उकेरा गया है।

शिक्षक की पहल पर आगे आए भामाशाह

प्रस्तर शिल्पकार और विद्यालय के सृजनधर्मी शिक्षक हेमंत जोशी के प्रोत्साहन से राउंड टेबल इंडिया के माध्यम से 36 लाख रुपयों की लागत से 6 कमरे तैयार किए गए है। एलएंडटी कंपनी द्वारा सीएसआर फंड से 4 लाख रुपयों की लागत से शौचालय तैयार करवाया गया है वहीं चौकसी ग्रुप व एलएंडटी द्वारा विद्यालय को

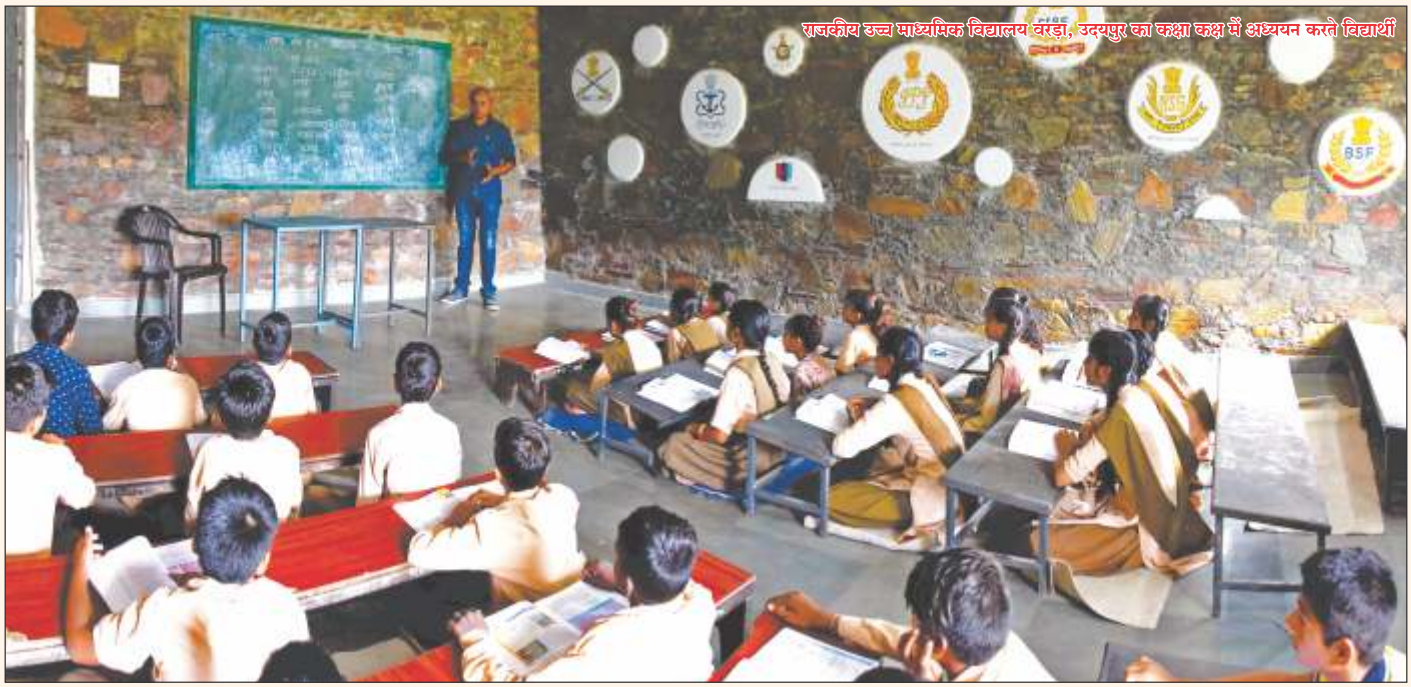
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर का कक्षा कक्ष में अध्ययन करते विद्यार्थी

लगभग तीन लाख रुपयों का फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार यहां पर रात्रि में विद्यालय परिसर को रोशन करने के लिए एलएंडटी द्वारा यहां पर 8 सोलर लाईट भी उपलब्ध कराई हैं। विद्यालय को आकर्षक स्वरूप देने के लिए प्रयास लगातार जारी है। खुद शिल्पकार होने से उनके द्वारा इस विद्यालय में कई कलात्मक चीजों को स्थापित किया गया है।

'नो बैग डे' का प्रभावी आयोजन

सरकारी स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की आनंददायी प्रविधियों के साथ सहशैक्षिक गतिविधियों के उपयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के बोझ से राहत दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत हर शनिवार को 'नो बैग डे' का इस स्कूल में प्रभावी आयोजन किया जा रहा है। पिछले दो शनिवारों में यहां पर 'राजस्थान को जानो' तथा 'भाषा कौशल विकास' थीम पर विविध

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर का कक्षा कक्ष

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर

गतिविधियों का आयोजन किया गया और शिक्षकों ने जहां विद्यार्थियों को राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताया तो खेल और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई के बोझ से मुक्त करते हुए जागरूक किया गया। इसी प्रकार इस दौरान शहर के जाने माने वास्तुकार सुनील लड्ढ़ा की वार्ता ने कला व वास्तुशिल्प की बारीकियों से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा, उदयपुर का खेल का मैदान

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

IRGY-Urban से शहरवासियों को भी मिलेगा रोजगार

सम्पत राम चान्दोलिया
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

नितिन शर्मा
अधीक्षण अभियंता, डीएलबी

विगत वर्षों में वैश्विक माहमारी कोविड-19 के चलते गांव हो अथवा शहर, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा, जो कोरोना की मार से बचा हो। कई जगह लोगों ने अपने परिजनों को खोया। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गईं। लोग अब तक इसके दंश से उबर नहीं पाए हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोजी-रोटी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तो महात्मा गांधी नरेगा के तहत सहायता प्रदान की, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लोग इससे अछूते रहे।

प्रदेश के शहरों की इस वेदना को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समझा और राजस्थान की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना की रूपरेखा तैयार कर इसे लागू करवाया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के बिन्दु सं. 6 पर की गई बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विषेश रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु 'मनरेगा' की तर्ज पर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) लागू की जा रही है।

इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। योजना के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की जा चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत पर्यावरण सरंक्षण कार्य, जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य, स्वच्छता एवं सेनीटेशन सम्बन्धी कार्य, सम्पति विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य, कन्वर्जेन्स कार्य, सेवा सम्बन्धी कार्य, हेरीटेज संरक्षण से सम्बन्धित कार्य एवं अन्य कार्य अनुमत हैं।

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का वेब पोर्टल www.irgyurban.rajasthan.gov.in भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है। मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिला कलक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा एवं योजना में प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों के क्रम में दिशा-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य स्तर से समस्त निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ई-मित्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संविदा के कुल 2 हजार 561 पदों पर भर्ती किये जाने बाबत समस्त जिला कलक्टर को दिशा-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं एवं भर्ती भी प्रक्रियाधीन है।

आदिनांक तक 213 निकायों में 9 हजार 593 कार्यो का चिह्नीकरण एवं 178 निकायों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। एक लाख, 90 हजार 703 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। जॉब कार्ड में 3 लाख 887 सदस्य एवं 18 हजार 707 परिवारों में से 27 हजार 414 श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग की गई है।

समस्त नगरीय निकायों को योजनान्तर्गत बजट आवंटित किया जा चुका है। सभी जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग एवं नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर योजना के क्रियान्वयन में पूरी सतर्कता के साथ मॉनिटरिंग करते हुए शहरी प्रदेशवासियों को इस योजना से लाभान्वित कर राहत देने के लिए निर्देशित किया गया है। श्रमिकों व मेट के नियोजन बाबत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर एवं नगरीय निकायों के स्तर पर विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भांति ही

प्रदेश के शहरों की इस वेदना को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समझा और राजस्थान की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना की रूपरेखा तैयार कर इसे लागू करवाया।

शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च किये जाएंगे। मजदूरी करने वाले श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए दूरदराज क्षेत्रों में जाना पड़ता था, योजना के तहत प्रदेश के शहरों में घर के आस-पास काम दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र के सदस्य इस योजना के लिए पात्र है। जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर जॉब कार्ड जारी किया जाता है। जॉब कार्ड आवेदन संबंधित नगरीय निकाय अथवा ई-मित्र केन्द्र पर होता है। बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा रहा है।

कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया

श्रम सामग्री अनुपात 75:25 में रहेगी। विशेष प्रकृति के कार्यों में श्रम : सामग्री अनुपात 25:75 जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक) से अनुमोदन उपरान्त कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी। स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन हेतु ऑनलाईन मस्टररोल जारी किए जाएंगे। अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मस्टररोल अवधि समाप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाईन राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP) IRGY-Urban MIS Portal) के माध्यम से कार्य स्थल पर श्रमिकों को पेयजल, गर्मियों में छाया हेतु टेन्ट एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्देश

नगरीय निकाय स्तर पर योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों में IRGY सेल गठन एवं हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। कार्य की मांग हेतु येजना के प्रपत्र-1 में आवेदन पत्र छपवाने का कार्य तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में योजना में पात्र श्रमिकों का आंकलन करवाते हुए रोजगार चाहने वाले परिवारों एवं व्यक्तियों का चिह्नीकरण (Identification) किया जाएगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी प्रदेशवासियों को रोजगार से जोड़कर हर हाथ को काम दिया जाएगा।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

देश में सबसे बड़ी
शहरी रोजगार गारंटी योजना

"कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने सम्बल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है।
अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है।
इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदद मिलेगी।"

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान में अब

राजस्थान सरकार शहरों के जरूरतमंद परिवारों को देगी

100 दिन का रोजगार

योजना के लिए सालाना

₹800 करोड़ का प्रावधान

अधिक जानकारी के लिए स्थानीय निकाय कार्यालय
या टोल फ्री नं.18001806127/181 पर सम्पर्क करें अथवा
www.lsg.urban.rajasthan.gov.in देखें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

शिक्षा के लिए ग्रामीणों ने किया दान : बदली विद्यालय की तस्वीर

कुमार अजय
सहायक निदेशक, जनसंपर्क, चूरू

भौतिक और शैक्षणिक स्तर के लिए मिसाल बना तोलियासर का सरकारी विद्यालय, भामाशाहों व ग्राम पंचायत के सहयोग से विद्यालय में पिछले डेढ़ साल में हुए एक करोड़ के कार्य और शिक्षकों, ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से विद्यालय की तस्वीर बदल गई है।

सैकड़ों छायादार, फलदार एवं फूलदार पौधों से हरा-भरा परिसर, पूरी तरह इंटरलॉक फर्श, झूले, वाटर कूलर, स्मार्ट क्लास समेत ऑनलाइन शिक्षण की बेहतरीन सुविधाएं, ई-लाईब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे, किचन गार्डन व लॉन जैसी सुविधाएं, सवेरे-सवेरे योग कक्षाएं और खेल गतिविधियां .... यह तस्वीर है चूरू जिले के सुजानगढ़ ब्लॉक के तोलियासर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां शिक्षकों के संकल्प और ग्रामीणों-भामाशाहों, ग्राम पंचायत के सहयोग ने सारी तस्वीर ही बदल कर रख दी है।

महज डेढ़ साल की कड़ी मेहनत के बाद यह विद्यालय भौतिक संसाधनों तथा अपनी शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक उलपब्धियों के लिए पूरे प्रदेश में एक मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, जन सहयोग, ग्राम पंचायत आदि के माध्यम से पिछले डेढ़ साल में करीब एक करोड़ रुपए के विकास कार्य विद्यालय में हो चुके हैं। ग्रामीणों की सोच में इतना बदलाव आया है कि मृत्युभोज जैसे अवसरों पर खर्च किए जाने वाला पैसा अब वे विद्यालय के विकास में लगा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को एक बेहतरीन माहौल मिले व उनका भविष्य सुरक्षित हो। बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय परिसर में ही 18 घंटे पढ़ाई की व्यवस्था से बेहतर परिणाम मिले हैं। स्कूल का पांचवीं से लेकर 12 वीं बोर्ड तक स्कूल का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत व उच्च गुणवत्ता का रहा है। नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह सब हुआ है विद्यालय के प्रधानाचार्य ने की पहल और शिक्षकों, ग्रामीणों व ग्राम पंचायत के अभूतपूर्व सहयोग से। जनवरी 2021 में जब उन्होंने यहां कार्यग्रहण किया, तो उन्हें स्कूल की व्यवस्थाओं में काफी सुधार की जरूरत महसूस हुई। तोलियासर ने भी विद्यालय की कायापलट का संकल्प लिया। एसडीएमसी और साथी अध्यापकों के सामने कार्ययोजना रखी, जिस पर सभी का सकारात्मक सहयोग मिला। जन सहयोग से एक-एक संसाधन जुटाना शुरू किया। मृत्युभोज आदि पर ग्रामीण काफी पैसा खर्च करते थे, उन्हें समझाया कि इस पैसे को स्कूल में लगाकर वे अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ग्रामीणों ने मृत्युभोज पर खर्च करने की बजाय अपने प्रियजनों की स्मृति में स्कूल के विकास के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। इससे विद्यालय में कक्षा-कक्ष, प्रवेश द्वार, पेयजल टंकी, वाटर कूलर, रसोईघर मय भोजन कक्ष, झूले, फर्नीचर, पक्षी चुग्गा घर, सरस्वती मन्दिर निर्माण आदि कार्य हुए। विद्यालय में हो रहे काम से प्रभावित, दूसरे गांवों के लोगों, रिश्तेदारों ने भी सहयोग किया। ग्रामीणों ने बच्चों के जन्मदिन, विवाह उत्सव, शादी की वर्षगांठ, पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर विद्यालय विकास के लिए अपनी हैसियत

अनुसार स्वेच्छा से सहयोग राशि देना शुरू कर दिया। जरूरतमंद विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखते हुए उनको विद्यालय गणवेश, फीस, स्वेटर, जूते, स्टेशनरी, बुक्स, नोटबुक्स नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

व्हॉट्सएप ग्रुप बनाकर शिक्षित ग्रामीणों, प्रवासी व्यवसायियों, नौकरीपेशा लोगों, पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ा गया। इससे विद्यालय गतिविधियों का प्रचार-प्रसार हुआ और ग्रुप सदस्यों का सहयोग विद्यालय विकास के लिए मिला। गतिविधियों के व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर प्रचार एवं ग्रामीणों से निरंतर संपर्क से नामांकन वृद्धि में भी काफी सहयोग मिला है। गांव के मौजीज लोग समय-समय पर विद्यालय में आकर व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। बदले माहौल से, ग्रामीण अब शिक्षा के लिए जागरूक होने लगे हैं। आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं को समय-समय पर सम्मानित किया जाता है तथा स्कूल में शिलापट्ट पर उनकी सूची लगाई गई है। विद्यालय में लगभग 150 फलदार व छायादार वृक्ष लगाकर 2 उद्यान विकसित किये गए हैं। गांव में घर-घर जाकर अध्यापकों व विद्यार्थियों नें लगभग 350 वृक्ष लगाये हैं।

पाठ्य सहगामी गतिविधियों पर भी जोर

विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है। रोज सुबह 5 बजे से स्वयं प्रधानाचार्य के नेतृत्व में योग, व्यायाम, दौड़ व खेल गतिविधियां हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 4 विद्यार्थी राज्य स्तर पर खेलों में भाग ले चुके हैं। विद्यालय में खिलौना बैंक की स्थापना कर खेल-खेल में सीखने को बढ़ावा दिया गया है।

राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय पुरस्कार

उत्कृष्ट भौतिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए इस विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-2021 के राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय चुना गया तथा गरिमामय राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के द्वारा प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल को पुरस्कृत किया गया है।

विशेष प्रयासों ने दिया बोर्ड में विशेष परिणाम

सुविधाहीन व कच्चे घरों में रहने वाले बच्चों के लिए घर में पढाई कर पाना मुश्किल काम है। स्कूल में ही सारी व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया गया। विद्यालय में ही पढ़ने-पढ़ाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले विद्यार्थियों के लिए प्रात: 4 बजे से रात 10 बजे तक, 18 घंटे विद्यालय में ही रहकर पढ़ने की व्यवस्था की गई। शिक्षकों के साथ, गांव के योग्य युवाओं से शिक्षण कार्य में सहयोग लिया गया। तीन पारियों में अलग-अलग विषय अध्यापकों की व्यवस्था की गई। शिक्षण प्रक्रिया को मॉनीटर किया गया, अध्यापन करवाया गया। विद्यार्थियों के नाश्ते, स्टेशनरी, बुक्स, नोट्स आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की गई। पर्याप्त संख्या में नए पंखे व ट्यूबलाइट

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर, चूरू में खेल गतिविधियां करते बालक-बालिकाएं

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर, चूरू में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर, चूरू का प्रांगण

लगवाए गए। बड़ी एलईडी फ्लड लाइट लगाई गई व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अवलोकन करते हुए प्रधानाचार्य, अध्यापकों व विद्यार्थियों से बात की और सरहाना कर प्रोत्साहित किया। इन सब प्रयासों से सत्र 2021-22 में प्रत्येक बोर्ड कक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। 10 वीं, 12 वीं के 57 विद्यार्थियों में से 52 प्रथम व 5 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 12 वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के परिणाम में उनके ही दसवीं के परिणामों की तुलना में 10 से लेकर 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। कोरोना काल में अध्ययन में हुए नुकसान को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के लर्निंग लॉस की पूर्ति करने के लिए सुप्रीम फाउण्डेशन जसवंतगढ़ के सहयोग से ग्रीष्म अवकाश में विशेष ब्रिज कोर्स चलाया गया।

तकनीक का मिल रहा है पूरा लाभ

विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व संचार क्रांति का पूरा लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन करवाया गया। अभिभावकों को भी एंड्रॉयड मोबाइल से ऑनलाइन अध्ययन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। दस कम्प्यूटर्स से सुसज्जित आईसीटी लैब में अध्यापकों ने गूगल, यूट्यूब विभागीय व अन्य एप्स के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास में कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नियो लिटरेसी अभियान के तहत गांव के प्रौढ़ व्यक्तियों को भी विद्यालय की आईसीटी लैब के माध्यम से कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं संचालन सिखाया गया। लैब का पूरा उपयोग शिक्षण में हो रहा है। विद्यालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की गई है और विभिन्न शैक्षणिक एप्स का उपयोग किया जा रहा है। नये सत्र से कक्षा 10 से 12 के लिए डिजिटल स्मार्ट इण्टर-एक्शन बोर्ड व बडे एलईडी यूडीएच स्मार्ट टी.वी लगवाकर नवीनतम तकनीक से अध्यापन की व्यवस्था की गई है। इन बोर्ड व स्मार्ट टी.वी के माध्यम से यूट्यूब सहित विभिन्न एप पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का लाभ भी विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर, चूरू का गार्डन

जागरूकता कार्यक्रम

कोरोना काल में शिक्षकों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया। कोरोना जागरूकता के अलावा समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जागरूकता, मतदाता जागरूकता, औषधीय पौधों के उपयोग, सड़क सुरक्षा, चाइनीज मांझा निषेध, धूम्रपान निषेध, नामांकन वृद्धि, कौमी एकता आदि के लिए अनेक अभियान चलाए व सेमिनार आदि का आयोजन किया गया। नामांकन वृद्धि के लिए गांवों मे रैली, रथ यात्रा, दीवारों पर बैनर, पोस्टर लगाकर जागरूकता पैदा की गई।

बांसवाड़ा

राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा योजना: नौनिहालों के भविष्य में निखार

कल्पना डिण्डोर
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, बांसवाड़ा

राजस्थान में शैक्षिक विकास को सम्बल प्राप्त होने के साथ ही भावी नागरिकों के व्यक्तित्व विकास की नींव मजबूत हो रही है। प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा-दीक्षा के लिए संचालित महात्मा गांधी विद्यालयों की भूमिका सराहनीय है जिनकी बदौलत जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के नौनिहाल सुनहरा भविष्य पाने की ओर अग्रसर हैं। बांसवाड़ा जिले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए यह योजना राजस्थान सरकार का वरदान सिद्ध हो रही है।

इस योजना के तहत बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर खान्दू कॉलोनी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थापित किया गया, बाद में वर्षो में ब्लॉक मुख्यालयों पर योजना का विस्तार करते हुए अब तक कुल जिले में 18 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्थापित कर बड़ी संख्या में बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

बोर्ड परीक्षाओं में फहराया कामयाबी का परचम

जिला मुख्यालय पर 2019-20 में स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गत तीन शैक्षणिक सत्रों में विद्यालय के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ शैक्षिक ऊँचाइयों को छूने का लक्ष्य भी विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया। इसी के परिणामस्वरूप अंग्रेजी माध्यम में पहली बार प्रविष्ट हुए छात्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पहली बार सत्र 2021-22 के परिणाम की उत्कृष्टता ने योजना के सफल क्रियान्वयन पर अपनी मुहर लगाई। इस विद्यालय से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट 45 छात्रों में से 42 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 25 प्रथम श्रेणी, 11 द्वितीय श्रेणी एवं 6 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

कोरोना काल में योजना बनी सहारा

राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम में राजकीय क्षेत्र में विद्यालय संचालन की योजना कोरोना काल में आमजन का सहारा बनी। कोरोना काल में ऐसे कई अभिभावक रहे जिनके रोजगार पर संकट उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव उनके परिवार के जीवनयापन तथा बच्चों की शिक्षा पर पड़ा।

ऐसा ही घटनाक्रम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खान्दू कॉलोनी में पढ़ रहे दो जुड़वा भाइयों के साथ भी घटित हुआ। विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र रवि भट्ट एवं राज भट्ट के पिता हेमन्त भट्ट के कोरोना काल में व्यापार बंद होने से आर्थिक संकट की परेशानियों से जूझना पड़ा लेकिन इस अवधि उनके दोनों जुड़वा बेटों की अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खान्दू कॉलोनी से होने के कारण निजी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक फीस अदा करने जैसी परेशानियों से राहत मिली तथा इन दोनों छात्रों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाते हुए रवि भट्ट ने 93.33 तथा राज भट्ट ने 92 प्रतिशत अंक दसवीं बोर्ड में अर्जित कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

निखरा हुनर प्रतिभाओं का

इसी तरह बांसवाड़ा सिन्टेक्स मिल में कार्यरत अल्पवेतन भोगी कार्मिक की पुत्री रेशमा गुप्ता भी 67.81 प्रतिशत अंक अर्जित कर महत्त्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित हुई है। इसी तरह चेल्सी पंचाल ने 85.4 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरे स्थान पर रही है। दसवी बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रा चांदनी, जनजाति वर्ग के छात्र दिव्यांशु मालवीया ने भी अंग्रेजी माध्यम में दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रा पूजा यादव 77.61 प्रतिशत, मनीष सिसोदिया 61 प्रतिशत, महेन्द्र सिसोदिया 67 प्रतिशत अंक अर्जित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दसवीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होकर योजना की सफलता को सिद्ध किया है।

भामाशाहों की रुचि ने दिया सम्बल

राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के भौतिक विकास में अब भामाशाह भी अपनी दिली रुचि दिखाने लगे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप विद्यालय द्वारा भौतिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया है।

बेटियों को आगे बढ़ने की 'शक्ति' देता अभियान

नज़ीर बनी बीकानेर की पहल, नवाचारों ने बढ़ाया बेटी का मान

राज्य सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'चुप्पी तोड़ो' जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीकानेर में 'शक्ति' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है-जन्म के समय घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, बेटी जन्म को उत्सव की तरह मनाना, बीकानेर को एनिमिया मुक्त बनाना, 'गुड टच-बैड टच' और 'माहवारी स्वच्छता प्रबंधन' के प्रति जागरूकता लाना। जिला प्रशासन की अगुवाई में चल रहा यह अभियान बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

एक अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2019-20 में जिले में एक हजार बच्चों की तुलना में 978 बेटियां जन्मीं, वर्ष 2020-21 में यह संख्या घटकर 970 और 2021-22 में 962 ही रह गई। इसी प्रकार नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अनुसार देश में 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 54.7 प्रतिशत तो बीकानेर में 59.4 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से ग्रसित पाई गई। इससे भी गंभीर बात यह थी कि 46.4 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं भी एनिमिक रिपोर्ट हुई।

इन सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए जिले में शक्ति अभियान की परिकल्पना की गई। इसके तहत पांच प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। इसकी पहली कड़ी के रूप में बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाने की परम्परा शुरू हुई। इसके तहत प्रत्येक बेटी के जन्म पर उसकी मां को उपहार स्वरूप 'सहजन फली' का पौधा और जिला कलक्टर के हस्ताक्षर युक्त शुभकामना संदेश दिया जाता है।

हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसंपर्क, बीकानेर

सहजन फली का पौधा पोषक गुणों से भरपूर है। यह गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण का संदेश देता है। वहीं पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी पौधे का महत्व है। इस सांकेतिक उपहार के पीछे यह मंशा भी है कि समाज को बेटी के जन्म पर गर्व की अनुभूति हो। जिला प्रशासन द्वारा सहजन फली के बीस हजार पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर तक समारोहपूर्वक वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे 'आई एम शक्ति कॉर्नर एवं वॉल'

विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम फहरा चुकी 12 महिलाओं की जीवनी से प्रेरणा लेकर बेटियां आगे बढ़ सकें तथा बेटों के मन से महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो सके, इसके मद्देनजर सरकारी स्कूलों में आई एम शक्ति कॉर्नर एवं आई एम शक्ति वॉल स्थापित किए जा रहे हैं। जिले का पहला आई एम शक्ति कॉर्नर राजकीय गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा पहला आई एम शक्ति वॉल

विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम फहरा चुकी महिलाओं की जीवनी

विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम फहरा चुकी महिलाओं की जीवनी

राजकीय शहीद मेजर जेम्स थॉमस स्कूल में स्थापित किया गया है।

आई एम शक्ति कॉर्नर में मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला, सिंधु ताई सपकाल, गुंजन सक्सेना, इंदिरा नुई, पीवी सिंधु, अवनि लेखरा, मेरीकॉम और लता मंगेशकर की जीवनी अंकित करवाई गई है। 'बुक कॉर्नर' में प्रेरणादाई पुस्तकें रखी गई हैं। इसमें कॉउंसलिंग कॉर्नर बनाया गया है तो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरुकता के लिए 'हाइजिन कॉर्नर' भी स्थापित किया गया है। इसमें चुप्पी तोड़ो, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग, बाल विवाह रोकथाम और मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जानकारी भी अंकित की गई है।

जहां आई एम शक्ति कॉर्नर की स्थापना बालिका विद्यालयों में की जा रही है वहीं सह शिक्षा विद्यालयों में 'आई एम शक्ति वॉल' स्थापित किए जा रहे हैं। जहां किसी सदृश्य दीवार पर इन बारह महिलाओं की जीवनी अंकित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा दूसरे चरण में 25 आईएम शक्ति कॉर्नर और 100 सरकारी स्कूलों में आई एम शक्ति वॉल बनाने का निर्णय लिया गया है।

शक्ति ई-मैगजीन से घर-घर पहुंचा रहे सफल महिलाओं की कहानियां

शक्ति अभियान के तीसरे घटक के रूप में शक्ति ई-मैगजीन का प्रकाशन किया जा रहा है। इस ई-मैगजीन के प्रत्येक अंक में राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम फहरा चुकी बीकानेर की बेटी की संघर्ष गाथा का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बेहतर मुकाम हासिल करने वाली बीकानेर की महिलाओं की जीवनी एवं स्कूली बालिकाओं की मौलिक रचनाओं का संकलन किया जाता है। इस ई-मैगजीन को ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक बनाए गए व्हाट्सएप्प ग्रुप्स के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस ई-मैगजीन के पहले अंक का विमोचन महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने किया, वहीं दूसरा अंक डेफ ऑलम्पिक की पदक विजेता बीकानेर की बेटी वेदिका शर्मा और तीसरा अंक दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने की रिकॉर्डधारी बीकानेर में ही जन्मी मेघा हर्ष द्वारा किया गया। ई-मैगजीन के प्रत्येक अंक का विमोचन एक बेटी द्वारा करवाए जाने का उद्देश्य उसके आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

'गुड टच-बैड टच' और 'माहवारी स्वच्छता प्रबंधन' के लिए कर रहे जागरुक

शक्ति अभियान के चौथे घटक के रूप में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जुलाई के प्रत्येक शनिवार को 'नो बैग डे' के अवसर पर 'गुड टच-बैड टच' और 'माहवारी स्वच्छता प्रबंधन' के प्रति जागरुकता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसके लिए सरकारी स्कूलों के एक हजार अध्यापकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इनमें पांच सौ पुरुष तथा इतनी ही महिलाएं हैं। यह मास्टर ट्रेनर जुलाई के प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में दोनों विषयों के प्रति अलख जगा रहे हैं। जरूरत के आधार पर अतिरिक्त ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी तक अच्छे और बुरे स्पर्श के प्रति जागरुकता के साथ माहवारी के दौरान स्वच्छता नहीं रखने से होने वाले नुकसान के प्रति सावचेत किया जा रहा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसे कॉलेजों में प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है।

पोषण के प्रति जगा रहे चेतना

सर्वे के दौरान मातृशक्ति का बड़ी संख्या में एनिमिक पाया जाना चिंताजनक है। इसके मद्देनजर स्कूल और आंगनबाड़ी की नामांकित बच्चियों में खून की कमी नहीं रहे, इसके मद्देनजर आवश्यकता और नॉर्म्स के अनुसार आयरन सिरप और टेबलेट दी जा रही हैं। इसके साथ 'प्रोपर डाइट' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके मद्देनर प्रत्येक स्कूली बच्चे के लिए प्रोपर डाइट चार्ट तैयार करवाया गया है साथ ही 'आयरन रिच फूड' के प्रति जागरुकता लाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए 'शक्ति' दिवस के अवसर पर इस अभियान के माध्यम से इन सभी गतिविधियों को और अधिक समन्वित तरीके से किया जाने लगा है।

विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम फहरा चुकी महिलाओं की जीवनी

कुल मिलाकर यह विश्वास जताया जा सकता है कि बेटी जन्म को प्रोत्साहित करने से लेकर बेटी को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर वातावरण बनाने के 'शक्ति' अभियान के दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बीकानेर में चलाया जा रहा यह अभियान पूरे देश के लिए नज़ीर बनेगा।

महिला श्रमिक द्वारा किये जा रहे श्रम कार्य

भीलवाड़ा: शत-प्रतिशत महिला मेट का नियोजन

हेमन्त छीपा
जनसम्पर्क अधिकारी, भीलवाडा

जिला प्रशासन की मजबूत इच्छाशक्ति और सक्षम नेतृत्व में भीलवाड़ा प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना में सभी मेट महिलाएं हैं। इसमें गांव की पढ़ी लिखी महिला को मेट के पद पर नियुक्त किया गया है। जिले में वर्तमान में लगभग 2 हजार महिला मेट काम कर रही है।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है, जो एक ऐतिहासिक पहल है।

महिला मेट नियुक्त होने से मनरेगा कार्यों में आ रही है पारदर्शिता

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को सफल बनाने के लिए यह प्रयास किया गया। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को मेट के पद पर लगाए जाने को हमने चुनौती के रूप में लिया। आमतौर माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा ईमानदार होती हैं। महिला मेट की नियुक्तियों से मनरेगा कार्यों में लगातार सुधार हुआ है और इसका रिजल्ट भी आने लगे हैं।

मनरेगा में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं, जिनकी मॉनिटरिंग पुरुष मेट द्वारा की जा रही थी। यह निर्णय लिया गया कि अगर मेट भी महिलाएं हो तो महिला श्रमिकों की समस्या आसानी से दूर हो सकेंगी। इसके लिए बेहतर योजना बनाकर कार्य शुरू करने के 40 दिन में सौ फीसदी महिला मेट लगाने में प्रशासन सफल रहा।

जब इस पहल पर आगे बढ़ने का काम शुरू किया तो जिले में लगभग 62 प्रतिशत महिलाएं मेट के रूप में कार्य कर रही थी। इसमें सबसे अधिक करेड़ा में 100 फीसदी और सबसे कम कोटड़ी में 26 प्रतिशत महिलाएं मेट थी। लेकिन अब जिले के सभी ब्लॉक में महिलाएं मेट के रूप में कार्य कर रही हैं। शुरुआत के बाद यह उपलब्धि हासिल करने में सिर्फ 40 दिन लगे।

धूप और गर्मी से बचाव के लिए बच्चों के लिए लगाए विशेष स्विस टेंट

जिले में महिला मेट के नवाचार के साथ ही एक और पहल की है। मनरेगा कार्यस्थल पर विशेष स्विस टेंट लगाए गए हैं। यह उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जिनके बच्चे छोटे हैं।

नरेगा के कार्य पर काम करने वाले श्रमिकों के कार्य पर निगरानी रखने के लिए महिला मेट द्वारा मोबाइल टेक्नलॉजी काम ली जा रही है। श्रमिक की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से जिले का डेटा नियंत्रण कक्ष तक भेजने का कार्य किया जा रहा है।

महिला मेट द्वारा समयावधि में कुशलतापूर्वक पूर्ण किये जा रहे है काम

योजनान्तर्गत जिले की 2299 महिलाओं का महिला मेट के पद पर कार्य करने के लिए चयन किया गया। इस कार्य के लिए गांव की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। महिला मेट द्वारा कार्य के व मेजरमेंट का रिकार्ड तैयार किया जाता है, साथ ही इस कार्य की जांच जेइएन, एईएन स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। महिला मेट के लगाने से यह कार्य आसान ही नहीं हुआ बल्कि समयावधि में पूरा होने लगा है। नरेगा के तहत जिले में लगभग 10658 कार्य प्रतिदिन चल रहे हैं। इन कार्यों पर प्रतिदिन लगभग 2 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

महिला मेट के लिए सुरक्षा सखी प्रशिक्षण एवं पंजीयन कार्यशालाओं का आयोजन

महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए शुरू की गई राज्य सरकार की क्रांतिकारी योजना सुरक्षा सखी योजना में भी जिला प्रशासन की पहल पर जिले की समस्त महिला मेट को जोड़ा गया है। साथ ही इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर महिला मेट एवं महिला सुरक्षा सखी प्रशिक्षण एवं पंजीयन कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत जिले में पुलिस विभाग के सहयोग से महिला मेट को महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ●

मरुक्षेत्रीय विद्यार्थियों का भविष्य निखार रहे हैं रेगिस्तानी छात्रावास

डॉ. उमेश शर्मा
जैसलमेर

रेगिस्तानी क्षेत्रीय बालिका छात्रावास देवीकोट में अध्ययन करती हुई छात्राएं

सामाजिक खुशहाली एवं आंचलिक विकास के लिए शिक्षा की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं के विकास एवं विस्तार की दिशा में योजनाएं-परियोजनाएं, कार्यक्रम एवं अभियान चलाए जा रहे हैं। इनसे प्रदेश में शैक्षिक विकास का ग्राफ उत्तरोत्तर ऊँचाई की ओर अग्रसर है। मीलों तक पसरे रेगिस्तानी क्षेत्रों में नौनिहालों को शिक्षा-दीक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के नवाचारी प्रयासों का सूत्रपात हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सरहद पर अवस्थित राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में इसी प्रकार का अनूठा प्रयास है रेगिस्तानी छात्रावासों का संचालन। अब इन रेगिस्तानी छात्रावासों का नाम बदल कर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस छात्रावास कर दिया गया है।

राजस्थान में कुल 11 आवासीय विद्यालय/छात्रावास संचालित हैं जिसमें से 7 आवासीय विद्यालय एवं 4 आवासीय छात्रावास हैं। जिनमें से 2 छात्रावास जैसलमेर में संचालित हैं। इनमें देवीकोट में बालिका छात्रावास तथा चाँधन में बालक छात्रावास संचालित है। ये छात्रावास वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत अनाथ, बेघर एवं बेसहारा बच्चों के लिए संचालित हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसार प्रवेश में वरियता निर्धारित है। इनमें उन्हीं बच्चों को प्रवेश प्रदान किया जाता है जिनकी पारिवारिक आय कम हो, बीपीएल श्रेणी के हों तथा जिनके आस-पास 10 किमी परिधि में कोई स्कूल नहीं हो। जिस ब्लॉक में छात्रावास संचालित है उसी ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित छात्रावासों में 50-50 बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रतिमाह, प्रति विद्यार्थी जेब खर्च हेतु 150 रुपए राज्य सरकार द्वारा सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में जमा किये जाते हैं, जबकि 1650 रुपए प्रतिमाह, प्रति विद्यार्थी के हिसाब से समसा द्वारा छात्रावासों को छात्र-छात्राओं के रहने, खाने, गणवेश इत्यादि हेतु दिये जाते हैं।

ये छात्रावास मरुस्थलीय बच्चों को घर से दूर घर जैसा वातावरण देने के साथ ही इनके भविष्य को सुनहरा बनाने की दिशा में बेहतर प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। इनमें नि:शुल्क आवास एवं पौष्टिक दूध, दोनों समय चाय-नाश्ता एवं पौष्टिक भोजन, चौबीस घंटे चौकीदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं वार्डन की नियुक्ति, पोषाहार, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधाएं, इन्वर्टर, आर.ओ. वाटर सिस्टम, पंखे, पलंग, बिस्तर, विद्यालय गणवेश, स्वैटर, कंघी, तेल, साबुन, जूते, मौजे, स्लीपर, रंगीन यूनिफार्म, रूमाल, नेल कटर, तौलिया, दूध, पेस्ट, टूथ ब्रश आदि सुविधाएँ, संगीत, खेलकूद, वाचनालय, स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार की नि:शुल्क सुविधा के साथ ही सिलाई, कम्प्यूटर, ब्यूटी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जीवन कौशल, शैक्षिक भ्रमण, नि:शुल्क स्टेशनरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्रीय बालिका छात्रावास देवीकोट में अध्ययन करती हुई छात्राएं

छात्रावासों में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन के साथ ही खेलकूद एवं साहित्यिक-सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए बहुआयामी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों में बच्चों के भविष्य निखार को देखकर गरीब ग्रामीण परिवारों की खुशियां बहुगुणित हो गई हैं। जिन बच्चों को स्कूली शिक्षा नसीब होना दिवास्वप्न ही लग रहा था उन्हें अब राज्य सरकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं। इन छात्रावासों ने विपन्नता अथवा अन्य कारणों से आहत परिवारों को राहत का अहसास कराने के साथ ही बच्चों के भविष्य की चिन्ता से मुक्त कर दिया है। यह छात्रावास पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में शिक्षा से वंचित जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में काफी मददगार सिद्ध हुए हैं।

सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स ग्राम खैरूणा, बूंदी

ओडीएफ प्लस कार्यक्रम से चमकने लगी है गांवों की सूरत

संतोष कुमार मीना
जनसंपर्क अधिकारी, बूंदी

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जिले में चलाए जा रहे ओडीएफ प्लस कार्यक्रम से गांवों की सूरत चमकने लगी है। ओडीएफ प्लस के द्वितीय चरण में 68 गांवो को चिन्हित किया गया है। इनमें खेरूणा पंचायत जिले की पहली मॉडल ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। शेष पंचायतों में कार्य प्रगति पर हैं। स्वच्छता के कार्यों के साथ इन गांवों में बच्चों के लिए खेल सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं।

ओडीएफ प्लस पंचायतें विकसित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शुरू किए गए इन कार्यों में सहयोग देकर ग्रामीण भागीदार बन रहे हैं।

ग्रामीण लेते हैं स्वच्छता की शपथ

ओडीएफ प्लस के तहत चिन्हित गांवों में स्वच्छता के कार्य शुरू होने के दौरान गांव को स्वच्छ रखने और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी

सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम, ग्राम खेरूणा

सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम, ग्राम खेरूणा

निभाने के लिए ग्रामीण शपथ लेते हैं। प्रशासन के साथ ही ग्रामीण भी उनके गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के कार्य में जुटने लगे हैं। घर परिवारों को घरों के आसपास गदंगी नहीं करने की समझाइश भी की जाती है।

यह हो रहे हैं कार्य

स्वच्छ भारत मिशन के ओडीएफ प्लस के तहत रामनगर गांव में मुख्य रूप तरल व ठोस कचरा प्रबंधन कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें तरल कचरा प्रबंधन के तहत गांव सोख पिट, मैजिक पिट, लीज पिट बनेंगे और ग्रे वाटर का उचित प्रबंधन किया जाएगा। शौचालयों में तकनीकी सुधार के लिए रेट्रो फिटिंग होगी। जहां नालियां नहीं है वहां नालियां बनाई जाएंगी। पानी के निस्तारण के लिए वाटर फिल्टर चेम्बर भी बनेंगे। वहीं ठोस कचरा प्रबंधन में नाडेब, वर्मी कम्पोस्ट, सामुदायिक कचरा पात्र, कचरा संग्रहण केन्द्र बनाया जाएगा तथा घर-घर से वाहन के माध्यम से कचरा संग्रहण होगा।

पाली : खदानों में भरी बरसात की एक एक बूंद बनेगी जीवनदायिनी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
जनसम्पर्क अधिकारी (से.नि.)

राजस्थानवासी ही सही मायने में पानी का मोल समझते हैं। हालांकि कहावतों में पानी के मोल होने का सामान्य अर्थ बहुत सस्ता होना होता है पर राजस्थान के संदर्भ में यदि कोई सबसे अधिक कीमती है तो पानी ही है। पाली वासियों की प्यास बुझाने में खदानों में भरे पानी की आपूर्ति अपने आप में किसी सराहनीय नवाचार से कम नहीं आंका जा सकता। सामान्यत: मीडिया में खदानों में भरे पानी में नहाते हुए डूबने के समाचार तो आते रहते हैं पर जीवनदायी बनती खदानों में भरी बरसात की एक-एक बूंद का महत्व पाली में जलापूर्ति से आसानी से समझा जा सकता है। पाली में पेयजल संकट के दौरान खदान में भरे पानी का आकलन किया गया तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि इन खदानों से पाली को प्रतिदिन 3 एमएलडी यानि कि 30 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जा सकती है और वो भी एक दो दिन नहीं बल्कि आरंभिक आंकलन के अनुसार पूरे दो माह यानि की जून के अंत तक।

पाली से 10 किमी दूर सुवानियां और मानपुर की खदान पर जिला प्रशासन, खान विभाग व जलदाय अधिकारियों ने समन्वय बनाते हुए पाली के जल फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की। पाली में अभी दो खदानें ही जलापूर्ति में सहभागी बन रही थी कि जाड़न खदान से भी पानी लाने की कार्ययोजना बन गई। पाली की जलापूर्ति की पूरी आवश्यकता इन खदानों में भरे पानी से नहीं हो सकती पर इस मायने में यह सराहनीय हो जाता है कि वाटर ट्रेन से आ रहे पानी के बाद भी कम पड़ रहे पानी की मांग इन खदानों के पानी से आसानी से हो सकती है। दूसरा यह कि एक तरफ संकट के दौर में खदानों का यह पानी जीवनदायी बनेगा वहीं खदानें खाली होने के बाद मानसून में वापिस भर जाएगी और यह पानी आपूर्ति जलापूर्ति में सहायक हो सकेगा।

दरअसल राजस्थान के लिए विपरीत भोगौलिक परिस्थितियां ही अब वरदान बनती जा रही है। तपता रेगिस्तान और धूलभरी काली-पीली आंधी ने राजस्थान को अक्षय उर्जा में अग्रणी बना दिया है। इसी तरह से अरावली व अन्य पहाडियां और रेगिस्तानी मिट्टी के धोरों के बीच बल्कि समूचे राजस्थान में बेशकीमती खनिजों के भण्डार भरे हुए हैं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी राजस्थान की समूची दुनिया में विशिष्ठ पहचान हो गई है। सकारात्मकता यह है कि पाली में खदानों से पानी की आपूर्ति नवाचार है।

राजस्थान खनिज प्रधान प्रदेश होने से खदानों की प्रचुरता भी है। ऐसी खदानें जिनमें अब खनन नहीं हो रहा है और उनका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं दिखता तो इन खदानों में भरी बरसात के पानी की एक एक बूंद का उपयोग जलापूर्ति में किए जाने की कार्ययोजना बनाई जा सकती है। इस पानी को पेयजल के विकल्प के रुप में व सिंचाई के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। पेयजल आपूर्ति चित्तोड़ की खदान और उदयपुर के रॉकफास्फेट की खदानों से किया जा रहा है। इस तरह से खदान का पानी जीवनदायी होने के साथ ही पानी की एक-एक बूंद प्रदेश के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

खदानों के पानी के उपयोग का जो प्रयोग पाली में किया है उसे विस्तारित कर गर्मियों में पानी की आवश्यकता को कुछ मात्रा में तो पूरा किया ही जा सकता हैं वहीं बरसात में जल संग्रहण की चैन विकसित भी की जा सकती है। बरसात से पहले खदानों का पानी उपयोग में ले लिया जाना चाहिए ताकि बरसात में पुन: पानी भरने से उसका उपयोग किया जा सके। इससे करोड़ो लीटर पानी की बचत हो सकेगी।

सरदार राजकीय संग्रहालय जोधपुर

जोधपुर की अभिनव पहल

इतिहास विषयक ज्ञान को समृद्ध करने की दिशा में व्यावहारिक कदम

डॉ. दीपक आचार्य
उप निदेशक, जनसम्पर्क, जोधपुर

स्कूली बच्चों को ऐतिहासिक विरासतों से रूबरू कराते हुए उनके इतिहास ज्ञान को समृद्ध करने की दिशा में जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल की गई है। इसमें विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जोधपुर स्थित मशहूर सरदार राजकीय संग्रहालय का अवलोकन कराने का नवाचार आरंभ किया गया है। इसकी शुरूआत जुलाई माह के दूसरे शनिवार से हो चुकी है। आरंभिक चरण में शिक्षा विभाग के माध्यम से जोधपुर शहर में संचालित विद्यालयों के बालक-बालिकाओं को शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ क्रमिक रूप से इस संग्रहालय में भेजे जाने की शुरूआत की गई है।

संग्रहालय में पुरातन इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराओं आदि के दिग्दर्शन के प्रति जनता में जागरुकता जगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे संग्रहालय में उपलब्ध विलक्षण एवं दुर्लभ थातियों से आम जन रूबरू हो सकेंगे, वहीं संग्रहालय के प्रति जनमानस में आकर्षण का भाव भी बढ़ेगा। बहुआयामी संग्रहालय के प्रति दर्शकों में आकर्षण जगाने के लिए जिला प्रशासन ने इस अभिनव पहल को अंजाम दिया है।

इस अभिनव पहल के शुभारंभ दिवस पर शहर की चार स्कूलों के छात्र-छात्राओं के समूहों ने संग्रहालय का अवलोकन किया। लघु फिल्म देखी। मारवाड़ तथा राजस्थान के इतिहास, परंपराओं, कला-संस्कृति और तत्कालीन परिवेश की झलक पायी। इनमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बा सहित पावटा, उदयमन्दिर एवं सर्राफा बाजार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समूह अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ आए तथा प्रदर्शित सामग्री एवं चित्रों के बारे में अपनी जिज्ञासाओं को शान्त किया।

संग्रहालय का अवलोकन करते हुए बच्चे

पाठ्यपुस्तकों में इतिहास के पन्नों से रूबरू होने वाले ये विद्यार्थी अपनी आँखों के सामने ऐतिहासिक तथ्यों और प्रदर्शित सामग्री को देख कर बेहद खुश हो उठे।

आँखों के सामने दिखा इतिहास

संग्रहालय अवलोकन कराने के लिए इन सभी बच्चों ने जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि जीवन में पहली बार अद्भुत एवं अविस्मरणीय ऐतिहासिक दृश्यों, सामग्री तथा चित्रों को देखने व इतिहास को जानने का मौका मिला है। इससे इतिहास विषयक उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ा है तथा बहुत कुछ पहली बार उन्होंने देखा है जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी।

संग्रहालय दिग्दर्शन का यह नवाचार निरन्तर जारी रहेगा। अपने अभिभावकों तथा सभी परिचितों को भी संग्रहालय देखने के लिए बच्चे प्रेरित करेंगे। इस ऐतिहासिक दुर्लभ खजाने को सभी को देखना चाहिए।

शिक्षा विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि सुविधानुसार स्कूली बच्चों को क्रमिक रूप से संग्रहालय भेजकर अवलोकन कराने का प्रबन्ध सुनिश्चित करें ताकि नई पीढ़ी इस दुर्लभ एवं संग्रहित विरासतों के बारे में जान सके।

संग्रहालय का अवलोकन करते हुए बच्चे

दुर्लभ ऐतिहासिक विरासतों का दिग्दर्शन

इन स्कूली बच्चों के समूहों ने देश-दुनिया में अपनी खासी पहचान रखने वाले इस संग्रहालय में कई दुर्लभ एवं ऐतिहासिक विरासतों की झलक देखी। इनमें विशेषकर स्मारक-वस्तु, लघुचित्र, शस्त्र-शस्त्रागार, मूर्ति कला, जैन कला, मानचित्र एवं साम्राज्य, सजावटी कला, शिकार एवं प्रकृति आदि दीर्घाओं के साथ ही चित्रों की दीर्घा तथा अन्य प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया।

मदर मिल्क बैंक

नवजात शिशुओं के लिए वरदान

राजकीय अस्पताल बारां का मदर मिल्क बैंक

विनोद मोलपरिया
जनसम्पर्क अधिकारी, बारां

राजकीय अस्पताल बारां का मदर मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए वरदान बनकर सेवाएं प्रदान कर रहा है। जिला अस्पताल स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक मां के दूध से वंचित नवजात शिशुओं को दानदाता मां का अमृत तुल्य दूध प्रदान करने के लिए 24 घंटे सेवाएं प्रदान कर रहा है। जिन महिलाओं के प्रसव के बाद दूध की कमी से नवजात शिशु को मां का दूध मिलने में परेशानी आती है ऐसे शिशुओं को दानदाता माताओं का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।

कैसे आती हैं दूध प्रदाता

आंचल मदर मिल्क बैंक में स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा दूध प्रदाता महिलाओं से संपर्क कर इसके उपयोग व महत्त्व से अवगत कराकर उन्हें दूध दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जिन महिलाओं को प्रसव के बाद दूध संबंधी समस्या हो वे पीड़ा से मुक्ति के लिए तथा कई जननी दूध के दान का महापुण्य व जीवनदायी मानकर स्वेच्छा से नियमित मदर मिल्क बैंक में दूध दान करती है।

अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर दूध की गुणवत्ता जांच

बच्चों को पौष्टिक व बीमारी रहित दूध उपलब्ध कराने के लिए प्रथम बार दूध के साथ ब्लड का सैंपल भी लिया जाता है। जिसमे ब्लड के तीन टेस्ट क्रमश: एचआईवी, हेपेटाइटिस, वीडीआरएल करने के बाद दूध कल्चर कर सुरक्षित दूध की प्रमाणिकता जांची जाती है तथा संग्रह करने योग्य दूध को उच्च क्षमता वाली मशीन से पाश्च्यूरिकृत कर बैक्टेरिया मुक्त किया जाता है। यदि ब्लड व दूध की जांच में खामी पाई जाती है तो दूध नहीं लिया जाता है। दूध प्रदाता से लेकर दूध संग्रहण व वितरण की प्रक्रिया तक मदर मिल्क बैंक के संबंधित कर्मचारियों को जीवाणु रहित दस्तानों के उपयोग के विशेष निर्देश है।

दूध की सुरक्षा के लिए व्यवस्था

दानदाता से प्राप्त अमृत तुल्य दूध को खराब होने से बचाने के लिए उच्च क्षमतावान मशीन में दूध को माइनस 18-22 डिग्री तापमान में 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा पाश्च्यूरिकृत दूध को 6 माह तक डी फ्रीज माइनस डिग्री में सुरक्षित किया जाता है। इन उच्च क्षमतावान मशीनों से दूध को निकालने के बाद दूध में 12 घंटे सामान्य फ्रीज तथा 72 घंटे आइसफ्रीज में खराब न होने की क्षमता मौजूद होती है।

जरूरतमंद शिशु को मिलता है दूध

मां के दूध से अभावग्रस्त शिशु को पोषण के लिए चिकित्सा इंचार्ज की अनुशंषा पर मदर मिल्क बैंक से दूध प्राप्त किया जा सकता है। पौष्टिक दूध के अभाव में शिशु के बार-बार बीमार होने पर शिशु को जब शिशु डॉक्टर को दिखाया जाता है तो वह बीमारी व कुपोषण की चपेट से बचाने के लिए मां का दूध पिलाने की सलाह देता है लेकिन मां के दूध की अनुउपलब्धता बताने पर जरूरतमंदो को दूध मिलने का स्थान बताने सहित जरूरत अनुसार दूध की अनुशंषा कर मदर मिल्क बैंक भेज दिया जाता है जहां नवजात शिशुओं को दूध आवश्यकतानुसार सुगमता से प्राप्त होता है।

मिल्क बैंक राज्य स्तर पर पुरस्कृत

आंचल मदर मिल्क बैंक को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग के लिए राज्य स्तर पर अवार्ड मिल चुका है। मदर मिल्क बैंक में मई 2022 तक 4641 दूध दानदाताओं से 9,56,099 यूनिट दूध एकत्रित हुआ है। जिसमें से 27 हजार 725 यूनिट दूध जरूरतमंद नवजात शिशुओं को वितरित किया जा चुका है। इसी क्रम में 3 हजार यूनिट दूध अजमेर भी भेजा गया है। मदर मिल्क बैंक में आवश्यकता के अनुसार 300 यूनिट दूध संग्रहित है। दूध चिरायुप्रदाता व रोग रक्षक साबित हुआ है। पालनागृह में पहुंचे नवजात शिशुओं में जन्म से मदर मिल्क बैंक स्थित दूध के सेवन से रोग मुक्त एवं तंदरुस्त बनाये रखता है। यह मिल्क बैंक मां के दूध से वंचितों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

JODHPUR IS DANCING TO THE TUNES OF EDUCATION

Golden period of educational development is shaping future of new generation.

Akanksha Palawat
Public Relations Officer, Jodhpur

The state government is making in untiring efforts through various mediums in the direction of shaping the future of the new generation and realizing the goal of self-reliant community. As per the orders of Chief Minister Shri Ashok Gehlot, many schemes and programs are being better implemented by the state government for educational development.

As a result of that, the golden period of educational development is on full swing in the state. In Jodhpur district, the coordinated efforts of the Education Department and various educational institutions are showing a significant impact. The district has achieved remarkable success and exceptional achievements in various schemes of the education department.

Bicycle Scheme

Free cycles are being provided by the state government to the girls studying in class 9 in a government school. Under this scheme, 15,972 cycles have been distributed in Jodhpur district in the session 2019-20. Similarly, 16,611 cycles in 2020-21 and 15,701 in 2021-22 have been received and distributed as per demand.

Gargi Award

Rs. 3000 is provided in two installments to the girl students of government and private schools who have secured more than 75 percent marks in class 10th. Under this scheme, out of the total beneficiaries in Jodhpur district in the session 2020-21, 2893 had been benefited from the first installment and 2335 from the second installment. Similarly, the process of online application for the session 2021 to 22 is in process.

Balika Protsahan Scheme

A lump sum amount of Rs 5000 is provided to the girl students of government and private schools who have secured more than 75 percent marks in class 12th. Under this scheme, the process of online application is going on in Jodhpur district for a total of 4054 beneficiaries in session 2020-21 and for session 2021-22.

Chief Minister's Humari Beti Scheme

While studying regularly in class 10 in government schools, a girl securing first-second position in the district and securing first place in BPL family with minimum of 75% marks and an orphan girl securing first position in the district with minimum 75% marks, a lump sum of Rs. 15 thousand for class 11 and 12 by the state government (for text books, stationery and uniform etc.) and Rs. 1 lakh (for preparation of competitive examinations) coaching and hostel fee is provided and after 12, up to post-graduation Rs. 25000 (for textbooks, stationery and uniform etc.) and Rs. 2 lakh (for preparation of competitive examinations) coaching and hostel fee is provided. In Jodhpur district, 19 girls have been benefited in session 2020-21 under the scheme and the process of application is going on for the current session.

Inspire Award

For the purpose of developing creative and innovative thinking of students studying in class 6 to 10 (age group 10 to 15), an amount of 10000 is provided to each student selected who apply online.

In the current session, a total of 6400 ideas were uploaded by district Jodhpur, in which Jodhpur was ranked eighth in the country, out of which 395 ideas have been selected. At present, selected project updation has been done by 195 selected students of last year.

Kali Bai Bheel Scooty Scheme

The first 100 meritorious girl students of economically backward class of general category, who have secured minimum 85% marks in 12th class and whose family income is less than 250,000, are provided scooty according to their preference (selected) by secondary education.

Under this scheme, 24 scooties received for the session 2018 to 19 were distributed on 13 May 2022 in Jodhpur district.

Similarly, the names of 48 girl students eligible for the session 2019 to 22 have been sent to the Directorate. And from 2020 to 21, online application forms have been taken from the girl students at the directorate level. The process of online application from girl students is going on for the session 2021 to 22.

पारम्परिक खेल सितोलिया

लोक संस्कृति की अनूठी विरासत : पारम्परिक खेल

एम. असलम
पत्रकार

प्राचीन काल से ही खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अपना महत्त्व रहा है। जिसमें समय एवं कालखंड के अनुसार बदलाव तो आए लेकिन वो आज भी जीवन की बुनियादी जरुरत के साथ ही शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिपूर्णता के लिए अपना अलग ही महत्व बनाए हुए हैं। सदियों से मनुष्य सुकून की तलाश में रहा है। खेल एक ऐसी गतिविधि है, जो शरीर को चुस्त-तंदरुस्त बनाए रखने के साथ ही मन-मस्तिष्क को एक ऐसा सुकून प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के आनंद उत्सव को बनाए रखता है।

कई परंपरागत एवं प्राचीन खेल है, जो आज भी खेले जाते हैं, आज भी लोक संस्कृति की वो अनूठी विरासत हैं। इसमें दड़ा भी एक खेल है, जो टोंक व बूंदी में मकर संक्रांति के दिन सदियों से खेला जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या अनगिनत होने के साथ ही देखने वालों की भी भारी संख्या आसपास नजर आती है। अर्जेंटीना के फुटबाल मैच से कम इसका उत्साह नहीं आंका जा सकता है। टोंक के आंवा कस्बे में इस खेल को देखने बाहर से भी लोग आते हैं। अपने आप में रोचक होने के साथ ही इस खेल से कई मान्यताएं भी जुड़ी हैं।

बहरहाल आवां का दड़ा कभी फौज में भर्ती परीक्षा के रुप में देखा जाता था, वहीं ये सौहार्द का प्रतीक आज भी बना हुआ है। इतिहासकार लिखते है कि 17 वीं शताब्दी के मध्य उनियारा पर रावराजा के पूर्वजों ने अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार ककोड़, नगर, बनेठा एवं आवां उनियारा के अधिकार में आ गए थे।

ये भी रहे लोक खेल

रुमाल झपट्टा, आइस-पाइस, गिल्ली-डंडा, आलमजी का आलम कोड़ा, छुप्पन-छुपाई, गुलाम लकड़ी, आंख मिचोली, अंधा भैंसा, इक्की दुक्की, सितोलिया, किल्ली किल्ली कांटा, लंगड़ी टांग का

पारम्परिक खेल गिल्ली डंडा

खेल, घोड़ी कच्ची के पक्की, अन्टे, भोरिया, टोल भोरा, जाल झपट, रस्सी कूद, रस्साकशी, पछट्टे, चंपो, चोसर, बोल मेरी मछली कितना पानी, लंगड़ी घोड़ी, चादर छुपाईया, थिरू बाटी थिरू, शतरंज, तांगा दौड़, मोटर दौड़, शोबदा बाजी का खेल, मेरी कमर पर कौन बुगला, जादू मंत्र का तमाशा, रींछ बंदर के तमाशे, कठपुतली का तमाशा, नाटक, चारबैत, नौबत बजना, बेत बाजी आदि खेल प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं।

पारम्परिक खेल कंचे

कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति

रंगमंच की दुनिया : नेट थियेट

ऐसा वर्चुअल रंगमंच जिसने राजस्थान के कलाकारों को तब मंच दिया जब सब कुछ बंद था

रोशनलाल शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार

कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब कलाकारों को मंच देने के लिए एक वर्चुअल रंगमंच की परिकल्पना की गई जो महज दो साल में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। खास बात ये है कि कोरोना काल में अस्थाई तौर पर शुरू हुई सभी व्यवस्थाएं, स्थितियां सामान्य होने के बाद लगभग बंद हो चुकी है लेकिन नेट थियेट स्थाई मंच हो गया है जिसके प्रति कलाकारों का उत्साह, प्रेम और कमिटमेंट है। हाल ही में नेट थियेट ने अपने सौ एपीसोड पूरे किए हैं। इस दौरान सैंकड़ों कलाकारों को नेट थियेट मंच दे चुका है और हजारों दर्शकों ने कलाकारों की कला का घर बैठे आनन्द प्राप्त किया है। इस मंच के जरिए नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, वार्ता, फाइन आर्ट ललितकलाओं को मंच मिला है।

राजस्थान का पहला आभासी (वर्चुअल रंगमंच) नेट थियेट की नींव 13 जुलाई 2020 में चारदीवारी यानी हेरिटेज सिटी में रखी गई जहां आज तक हर शनिवार अनवरत प्रस्तुतियां दी जा रही है। जनमानस के साथ कलाकारों को मंच में एक अजीब सी कुंठाए पांव पसार रही थी, उसी दौरान अनिल मारवाड़ी ने वर्चुअल रंगमंच की परिकल्पना की और अपने घर की छत को रंगमंच की आकार-आकृति देकर कलाकारों को ऑनलाइन प्रस्तुति देने के लिये एक आभासी मंच तैयार किया।

कारवां बनता गया

विभिन्न विधाओं से जुड़े कलाकारों को इस वेब रंगमंच से जोड़ने, परियोजना को मूर्त रूप व कला प्रस्तुति का सफल निष्पादन की जिम्मेदारी राजेन्द्र शर्मा राजू ने उठाई है। मनोज स्वामी, धृति शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, आलोक पारीक, नीरज सरना, मुकेश सैनी, अंकित शर्मा, अर्जुन आर्य, विष्णु जांगिड़, सौरभ कुमावत, अंकित जांगिड़, रोहित रावत, अजय शर्मा, किशन कुमार आदि सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। ईश्वर दत्त माथुर, गुरमिंदर सिंह रोमी, सुनील, सुशीला शर्मा आदि वरिष्ठ कलाकारों एवं पत्रकारों के मार्गदर्शन में नेट-थियेट और कलाकारों की प्रस्तुति सफलता के साथ दर्शकों तक पहुच रही है।

रंग भी है, मंच भी है, लेकिन दर्शक ऑनलाइन हैं

यह रंगमंच देश-दुनिया में इस मायने में अलहदा है कि इस रंगमंच की दर्शक दीर्घा नहीं है जबकि रंगमंच का अहम हिस्सा दर्शक दीर्घा ही होती है। स्टेज, पर्दे, लाइट, साउंड रंगमंच के सभी तत्व मौजूद हैं बस असीमित दर्शक ऑनलाइन हैं। इस वर्चुअल थियेटर के माध्यम से कलाकारों की प्रस्तुति को दर्शकों के हाथों में पहुंचाने का अनवरत सार्थक प्रयास है। जो दर्शक जो रंगमंच तक नहीं पहुंच पातें वहीं हजारों दर्शक मोबाइल के माध्यम से अपने स्थान पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं।

कलाकार द्वारा मनमोहक प्रस्तुति

नेट-थियेट लगभग 50 हजार से अधिक दर्शकों तक पहुंच चुका है तथा 10 हजार से अधिक लोगों ने कार्यक्रम को देखा है। नाटक बलिदान को 28 हजार दर्शकों ने देखा है। देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त कलाकारों का डांस, ड्रामा, संगीत, नृत्य की 80 से अधिक प्रस्तुतियों का सफल मंचन नेट थियेट में किया जा चुका है। ख्याति प्राप्त कलाकार पद्मश्री बिस्मिल्लाह खां के पौत्र फतेह अली खां (शहनाई), साबरी ब्रदर्स (कव्वाली), अहमद हुसैन-मोहम्मद हुसैन (गजल) आदि राजस्थान के नामचीन कलाकार और पत्रकार इस मंच पर अपनी सफल प्रस्तुतियां दे चुके हैं। नेट थियेट की परिकल्पना अपने आप में अद्वितीय है।

कोटा का अभेड़ा महल

कोटा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अभेड़ा महल। यह कोटा के पर्यटक स्थलों में से एक है। महल के पीछे बड़ा तालाब है जिसमें वर्षभर पानी भरा रहता है। यहां पुरुष तथा महिला घाट बने हुए हैं। मुगल गार्डन शैली में महल के सामने पार्क बना हुआ है। महल के तीन तरफ पानी भरा रहता है जिसमें घूमने के लिए पथ बनाये गये हैं, जहां पर्यटक भ्रमण करते हैं। यह महल तीन मंजिला है। महल के अंदर राजपूत शैली के लघु चित्र बने हुए हैं।

आलेख एवं छाया : हरिओमसिंह गुर्जर

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

तब

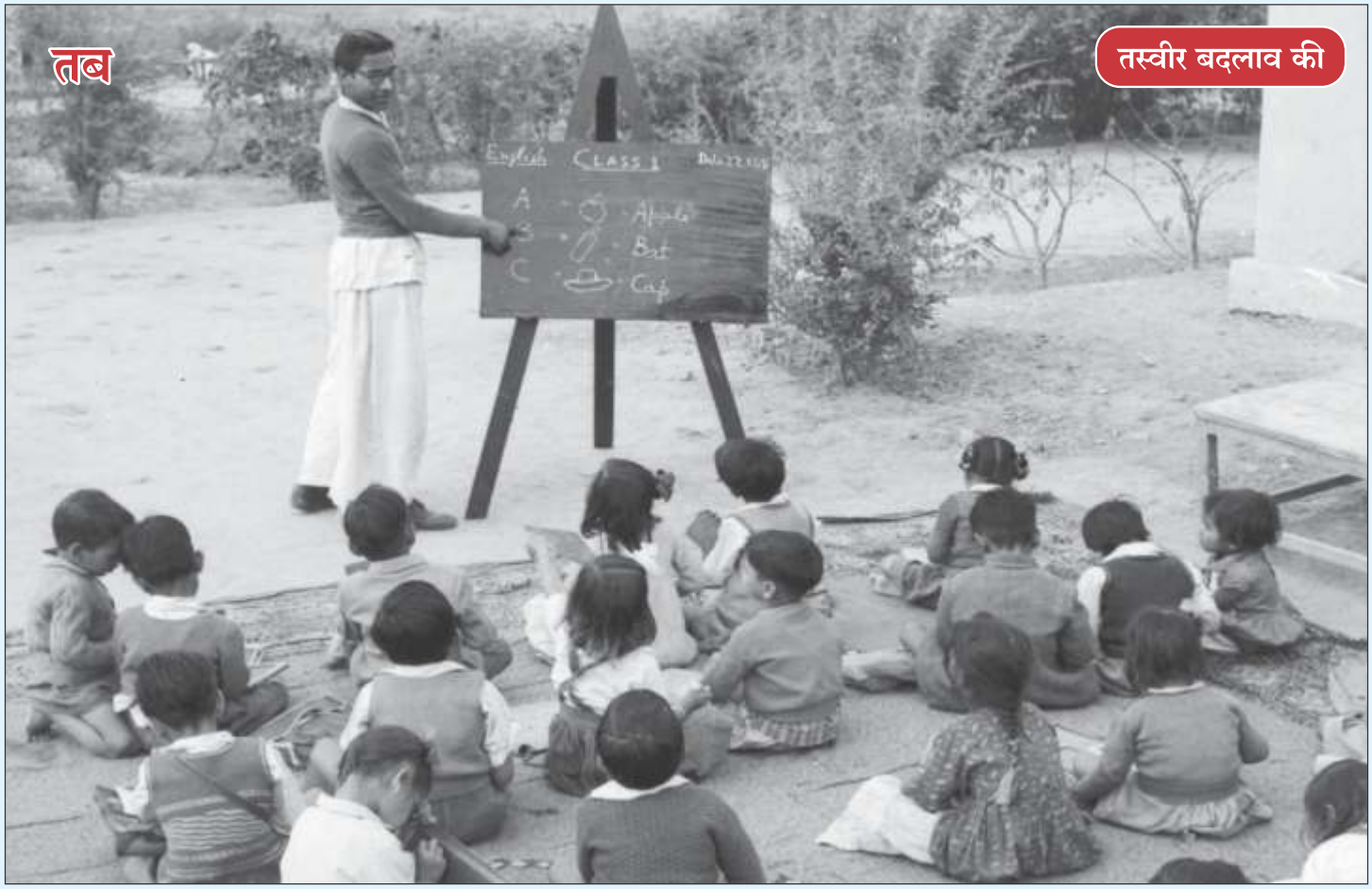

अब

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये ● 5,00,000 प्रतियां